R.N.I. : UPHIN/2012/52437
Website : www.mantrabharat.com
संस्करण : प्रयागराज
वर्ष : 15
अंक : 09
पृष्ठ : 8
मूल्य : 1.00
बुधवार, 17 सितम्बर, 2025

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन संख्या : एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

प्रयागराज, लखनऊ, ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ व गोरखपुर से प्रसारित

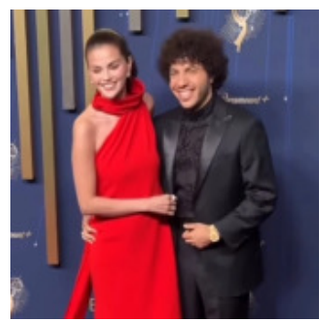

3 भाजपाइयों ने केक काट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ... 5 डीएम की अध्यक्षता में आईजीआरएस की बैठक ... 7 एमी में मंगेतर बेनी ब्लैंको के साथ सेलेना ...

विकास नहीं विनाश कर रहा मास्टर प्लान हरिद्वार में फूटा व्यापारियों का गुस्सा

देहरादून **(एजेंसी)**। राज्य व्यापार मण्डल (रजि0) उत्तराखंड द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कॉरिडोर, मास्टर प्लान के नाम पर तोड़-फोड़ बस अड्डा, जहान्वी मार्किट शिफ्टिंग को लेकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौटाला ने कहा की पिछले दो तीन वर्षो से शासन-प्रशासन द्वारा व्यापारियों में एक भय का माहौल बना दिया है ना जाने कब प्रशासन व्यापारियों को बेरोजगार कर देगा, किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या विस्थापन होने पर अब व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, यदि शासन प्रशासन ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की तो व्यापारी आने वाले सावन मेले एवम कुम्भ मेला में प्रशासन का सहयोग नहीं करेगा।

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने कहा की विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे, व्यापारियों कई वर्षो तक मेहनत कर अपना व्यापार स्थापित करता है अपना परिवार चलता है और वहीं शासन के जिम्मेदार अधिकारी चंद मिनटों में उसे उजाड़ने की योजना बना देते है जो व्यापारी हरकी पौड़ी में व्यापार कर रहा है वह अन्य स्थान पर व्यापार कैसे करेंगा, जो क्षेत्र पर्यटन वहिन है वहां व्यापारी किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होगा, शासन-प्रशासन को व्यापारियों की पीड़ा समझनीं चाहिए, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय प्रजापति व प्रदेश महामंत्री अतुल गोसाई ने कहा कि सरकार व्यापारियों को उजाड़ने का षड्यंत्र कर रही है यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ा जा रहा है वहीं मेला लैंड पर बहारी क्षेत्रों से आये लोगों को संरक्षण दिया जा रहा अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तों हरिद्वार से पूरे प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा।

प्रदेश सयुंक्त महामंत्री दीपक गौनियाल व युवा जिलाध्यक्ष विशाल गोस्वामी ने कहा की हरकी पौड़ी से अभी बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर है जगजीतपुर जाने से वो दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी जो की स्थानीय जनता व श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है प्रदेश प्रचार सचिव गोकुल सिंह रावत व महानगर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा की यदि मेला प्रशासन व जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान योजना में बदलाव नहीं किया तों व्यापारी और जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, उक्रांद पूर्व लोक सभा प्रत्याशी मोहन सिंह असवाल ने कहा की यदि जल्द व्यापारियों की समस्या का सज्ञान नहीं लिया गया तों यूकेडी व्यापारीयों के साथ मिल कर देहरादून सचिवालय कूच करेगी, विरोध करने वालों में मुख्य रूप से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष भागवत अग्रवाल, तेजप्रकाश साहू, चंद शेखर गोस्वामी प्रदेश सचिव जसवंत बिस्ट, प्रदेश सचिव राजकांड पाल, हरकी पौड़ी अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, नितिन शर्मा, गोकुल सिंह रावत, कनखल इकाई महामंत्री दिनेश कालरा, सोनल गर्ग, मधुर अरोड़ा, विनोद राठौर अध्यक्ष जमालपुर व्यापार मण्डल, बाबू लाल अध्यक्ष रावली मेहदूद व्यापार मण्डल, सागर प्रजापति, नितिन शर्मा, सौरभ अरोड़ा, रवि जैन, राकेश बिस्ट, रिक्की अरोड़ा, रवि शर्मा, नरेश चंयाना, मनोज वश्नोई, डॉ विष्णु दत्त वर्मा, मास्टर मुन्ना लाल, मोनू शर्मा, विकास शर्मा, विक्की अरोड़ा, नितीश मल्होत्रा, निखिल राजपाल, प्रदीप अग्रवाल, दीपक सिंघल, राजेश सिंघल, देव चौटाला, सागर बेनीवाल, पंकज सिंघल, मोनू शर्मा, राकेश बिस्ट आदि बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

हवा में उपचारः कैसे वृक्ष-उत्सर्जित टरपीन मानव शरीर-क्रिया और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं ञअजय सोनकर

प्रयागराज। विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार सोनकर ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया है कि वृक्षों से उत्सर्जित फाइटोनसाइड्स, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक मानव स्वास्थ्य को समर्थन देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन यौगिकों में अल्फा-पिनीन और लिमोनीन जैसे टरपीन शामिल हैं, जिन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभों के लिए तेजी से मान्यता मिल रही है।

डॉ. सोनकर के अनुसार,फाइटोनसाइड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, विशेषकर नेचुरल किलर (ञ) कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ाकर। ये कोशिकाएँ संक्रमणों और घातक (कैंसरजन्य) परिवर्तनों के विरुद्ध शरीर की पहली रक्षा-पंक्ति होती हैं। उन्होंने कहा, 'वृक्षों से उत्पन्न वाष्पशील यौगिकों के संपर्क से प्रतिरक्षा कार्यप्रणाली में सुधार होता है, तनाव हार्मोन (जैसे कॉर्टिसोल) का स्तर घटता है और शरीर में संतुलन (होमियोस्टैसिस) को प्रोत्साहन मिलता है।'

प्रतिरक्षा संबंधी लाभों के अतिरिक्त, डॉ. सोनकर ने फाइटोनसाइड्स के न्यूरो-साइकोलॉजिकल प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। इन यौगिकों से समृद्ध वन्य वातावरण में नियमित संपर्क को कम चिंता, बेहतर मनोदशा और गहन नींद की गुणवत्ता से जोड़ा गया है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकियाँ मानव कल्याण पर बहुआयामी प्रभाव डालती हैं।

डॉ. सोनकर ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि वनों का संरक्षण केवल एक पारिस्थितिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का भी अभिन्न अंग होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में फाइटोनसाइड्स की निरंतर उपस्थिति इस बात का ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है कि मनुष्य और वनों के बीच चिकित्सीय अंतःक्रिया पर अंतःविषयक शोध को और आगे बढ़ाया जाए।

मोदी सरकार का नशा मुक्त भारत का संकल्प अमित शाह बोले- 2047 तक खत्म होगा खतरा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश से सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के पैमाने में बदलाव किया जाए ताकि आने वाले दिनों में और अधिक सफलताएँ मिलें।

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2047 में एक महान भारत के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की। एक ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा। अगर हमें ऐसा भारत बनाना है, तो अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी महान राष्ट्र की संकल्पना, उसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खोखली हो जाएँगी, तो देश भटक जाएगा... दुर्भाग्य से, वे दोनों क्षेत्र जहाँ से दुनिया भर में नशे की आपूर्ति होती है, हमारे नज़दीक ही हैं... इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ें।

शाह ने कहा कि तीन तरह के कार्टेल होते हैं, एक वो कार्टेल जो देश के सभी एंट्री पॉइंट्स पर काम करता है, दूसरा वो कार्टेल जो एंट्री पॉइंट से राज्य तक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्टेल है और तीसरा वो कार्टेल जो राज्यों में पान की दुकान या गली के नुक्कड़ पर ड्रग्स बेचने तक काम करता है। इन तीनों तरह के कार्टेल्स पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। मेरा मानना है कि ऐसा तभी हो सकता है जब यहां बैठे लोग तय कर लें कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है।

अमित शाह ने कहा कि भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यर्पण, ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब समय आ गया है कि जो लोग विदेश में बैठकर यहाँ नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें हमारे कानून के दायरे में लाया जाए। सीबीआई ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी एएंडटीएफ अध्यक्षों से अनुरोध करता हूँ कि वे सीबीआई निदेशक से संपर्क करें और प्रत्यर्पण के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, जो न केवल नशे, आतंकवाद, गिरोहों, बल्कि हर चीज़ के लिए उपयोगी हो। यह बहुत ज़रूरी है और जिस तरह प्रत्यर्पण ज़रूरी है, उसी तरह व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ निर्वासन भी ज़रूरी है। जिन लोगों को आपने यहाँ जेल में रखा है, वे किसी न किसी तरह से यहाँ से कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, उन्हें निर्वासित करने की व्यवस्था का रास्ता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गृह विभाग इसके लिए एक एसओपी भी जारी करने वाला है।

बिहार के छात्रों की मौज! नीतीश सरकार ने शिक्षा ऋण से हटाया ब्याज का बोझ

पटना **(एजेंसी)**। चुनावी साल से पहले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी साझा की और इसे इच्छुक छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने वाला कदम बताया। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदक को मात्र 01 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। नीतीश ने कहा कि साथ ही 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) में तथा 02 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद झुकी दिल्ली सरकार ईवी ग्राहकों को मिलेगी 140 करोड़ की सब्सिडी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी के लगभग 140 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान का भुगतान करने के लिए तैयार है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने पुष्टि की है कि विभाग दो वर्षों से जमा हुए बकाया भुगतान के लिए सभी सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन करेगा। यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की गई है।3 सितंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर वादा किए गए सब्सिडी के वितरण में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि प्रक्रियागत देरी भुगतान में बाधा नहीं बननी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में समय

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों के निपटान के लिए इनका सत्यापन करेगा। एक अधिकारी के अनुसार, सरकार लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रही है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन सितंबर को दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी का वितरण करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा था कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई इसलिए बकाए के भुगतान की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सका।

आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2020 में ईवी नीति की शुरुआत के बाद से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है, जिसमें 1.09 लाख दोपहिया वाहन और 83, 724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की थी।

शिक्षकों के अनुभव पर योगी सरकार का जोर

टीईटी अनिवार्यता के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्देश

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

पिछले पाँच दिनों में, उत्तर प्रदेश में दो शिक्षकों–जो चालीस और पचास के दशक के अंत में थे–ने आत्महत्या कर ली है। कथित तौर पर वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के दबाव का सामना नहीं कर पाए। उनके परिवारों का आरोप है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारी को लेकर तनाव में थे।

1 सितंबर, 2025 को, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाया कि पाँच साल से अधिक की सेवा शेष रहने वाले सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया था, लेकिन इसका अखिल भारतीय प्रभाव है, जिससे लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हैं–जिनमें से लगभग दो लाख अकेले उत्तर प्रदेश में हैं।

असम में हिंदुओं की जमीन दूसरे समुदाय को अवैध तरीके से ट्रांसफर कर रही थी अधिकारी नुपुर बोरा

मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा ने पड़वाया छापा, करा दी गिरफ्तारी

गुवाहाटी **(एजेंसी)**। असम में हाल ही में सामने आए भूमि घोटाले ने राज्य की प्रशासनिक ईमानदारी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। गुवाहाटी में गिरफ्तार की गई असम सिविल सेवा (एसीएस) की युवा अधिकारी नुपुर बोरा केवल छह वर्ष पहले ही सेवा में शामिल हुई थीं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार का जाल केवल अनुभवी अधिकारियों तक सीमित नहीं, बल्कि नई पीढ़ी भी इसकी चपेट में आ रही है।

हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सतर्कता प्रकोष्ठ ने नुपुर बोरा के गुवाहाटी स्थित दो फ्लैटों पर छापा मारकर लगभग एक करोड़ रुपये नकद, हीरे और लाखों की ज्वेलरी बरामद की। उनके खिलाफ आरोप है कि बरपेटा जिले में कार्यकाल के दौरान उन्होंने अवैध भूमि हस्तांतरण में भूमिका निभाई, जिसमें कथित तौर पर हिंदू समुदाय की ज़मीन को दूसरे समुदाय के नाम पर स्थानांतरित किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि यह अधिकारी पिछले छह महीनों से सरकार की निगरानी में थी और उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें लगातार आ रही थीं।

देखा जाये तो असम में भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय संतुलन और सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न भी है। बरपेटा और अन्य निचले असम के ज़िले लंबे समय से 'बांग्लादेशी घुसपैठियों' के ठिकाने माने जाते रहे हैं। ऐसे में भूमि का अवैध हस्तांतरण केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि हाल ही में राज्य कैबिनेट ने अंतर-धार्मिक भूमि लेनदेन के लिए असम पुलिस की विशेष शाखा से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने असम दौरे में इस खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अवैध प्रवासियों से राज्य की जनसांख्यिकी बदलने का खतरा वास्तविक है। इस परिप्रेक्ष्य में नुपुर बोरा का मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक बड़े जनसांख्यिकीय संकट में योगदान करने जैसा है।

हम आपको यह भी बता दें कि

नुपुर बोरा का सोशल मीडिया प्रोफाइल उनकी जीवनशैली, फैशन और यात्रा के शौक को दर्शाता है। लेकिन इन सबके पीछे जो भारी-भरकम अवैध संपत्ति मिली, वह इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर धन संचय और दिखावटी जीवनशैली का आकर्षण किस तरह नौजवान अधिकारियों को भी भ्रष्ट कर रहा है।

देखा जाये तो यह स्थिति दोहरा खतरा पैदा करती है। ऐसे घटनाक्रमों से भ्रष्टाचार की संस्थागत जड़ें गहरी होती जाती हैं और सामाजिक विभाजन तथा असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री सरमा का यह कहना कि 'राजस्व विभाग की भ्रष्टाचारग्रस्त व्यवस्था' को साफ करना होगा, इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि समस्या केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। यह मामला गहरी जमी हुई उस संरचना को उजागर करता है, जिसमें भूमि माफिया, राजनीतिक हित और प्रशासनिक उदासीनता एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं।

देखा जाये तो असम का यह प्रकरण केवल भ्रष्टाचार का सामान्य मामला नहीं है। यह उस गहराई को दिखाता है जहां व्यक्तिगत लालच, अवैध प्रवास और सांस्कृतिक असुरक्षा आपस में उलझ भी जाते हैं। नुपुर बोरा की गिरफ्तारी सरकार के लिए केवल एक सफलता नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह नहीं बनाया गया, तो असम की जनसांख्यिकीय चुनौतियां और गंभीर रूप ले सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की असली परीक्षा यही है कि वह नौकरशाही की ईमानदारी, भूमि की पवित्रता और समाज की सुरक्षा को एक साथ कैसे संतुलित करती है।

इसके अलावा, असम में भूमि से जुड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरी परतें खुलती हैं। नुपुर बोरा प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदू समुदाय की ज़मीन को व्यवस्थित तरीके से दूसरे समुदाय के नाम पर स्थानांतरित किया जा रहा था। यह बात जगजाहिर है कि असम लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के दबाव से जूझ रहा है। विशेषकर निचले असम के ज़िलों–बरपेटा, धुबरी, गोराइमारी में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। ज़मीन का अवैध हस्तांतरण कोई सामान्य भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है जिसके ज़रिए जनसंख्या संतुलन को बदला जा सके और हिंदुओं को धीरे-धीरे विस्थापित किया जा सके।

परमार्थ निकेतन में श्रीमद्भागवत भाव कथा का शुभारम्भ

गुरु नानक देव के ज्योति-ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओजोन परत संरक्षण हेतु समर्पित, समाज में प्रेम व करुणा संचार यही भागवत कथा का सार

मंत्र भारत संवाददाता

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन, माँ गंगा के पावन तट पर स्वामी चिदानन्द सरस्वती के दिव्य सान्निध्य में श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण महाराज के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत भाव कथा का मंगलमय शुभारम्भ हुआ। गंगा की गोद में भागवत कथा का श्रवण आध्यात्मिक आनन्द के साथ जीवन को धर्म, सेवा और संस्कारों से जोड़े रखने की प्रेरणा भी है। स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन की परम मार्गदर्शक है, जो हमें ईश्वर-भक्ति, मानवता की सेवा और प्रकृति संरक्षण का सन्देश देती है।

आज सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु, गुरु नानक देव के ज्योति-ज्योत दिवस पर परमार्थ निकेतन से उन्हें कोटि-कोटि नमन किया। गुरु नानक देव ने संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग परोपकार, सेवा और भाईचारे से होकर जाता है। उन्होंने समाज को समानता, करुणा और प्रेम का अमूल्य संदेश दिया। गुरू नानक देव ने सम्पूर्ण मानवता को पउणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु का दिव्य संदेश दिया। आज भी गुरूवाणी हमें यह

स्मरण कराती हैं कि वायु हमारे गुरु हैं, जल हमारे पिता और धरती हमारी माँ है।

आज के पर्यावरणीय संकट में हमें यह भी बताती है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज 16 सितम्बर, विश्व ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओजोन परत संरक्षण हेतु समर्पित है। यह दिन हमें उस अदृश्य परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण परत की याद दिलाता है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह ओजोन परत प्रकृति की वही ढाल है जिसने धरती पर जीवन को सम्भव बनाया। यदि यह परत न हो, तो मानव ही नहीं, संपूर्ण जैविक जीवन विकिरणों की घातक लपटों में झुलस जाए। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन परम्परा ने सदैव हमें संदेश दिया कि प्रकृति ही परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। वृक्ष हमारे प्राण हैं, नदियाँ हमारी जीवनधारा हैं और वायु-आकाश हमारा जीवन-सहचर। गुरु नानक देव ने जिस धरती को 'माता' कहा और जिस जल-वायु को गुरु-पिता कहा, वह आज हमें पुकार रही है कि हम केवल भक्ति में ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी प्रकृति को पूजें। पौधारोपण, प्रदूषण-नियंत्रण और संसाधनों का संयमित उपयोग ही सच्ची सेवा और सच्चा धर्म है।

उन्होंने कहा कि 'श्रीमद्भागवत भाव कथा केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि धरती और समाज के कल्याण का मार्ग भी दिखाती है। कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी वृक्ष, गो, गंगा और पर्वत की रक्षा की। उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आज हमें ओजोन परत जो आधुनिक युग में हमारी वैश्विक जीवन-रेखा है उसका संरक्षण करने हेतु आगे आना होगा।

श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन का अमृत है और धर्म व अध्यात्म का सार भी है। गंगा के पावन तट पर जब कथा का श्रवण करते हैं तो यह श्रोताओं के कानों में ही नहीं, बल्कि उनके हृदय में भी गूंजता है और आत्मा को जागृत करता है।

उन्होंने कहा कि भागवत कथा हमें भगवान श्रीकृष्ण की उन लीलाओं की याद दिलाती है, जिनमें केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा का गहरा संदेश छिपा है। वृक्षों का संरक्षण, गौसेवा, नदी-जल की पवित्रता और समाज में प्रेम व करुणा का संचार यही भागवत कथा का सार है।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने श्रद्धालुओं का आह्वान किया कि कथा का श्रवण केवल सुनने तक सीमित न हो, बल्कि जीवन में उसका आचरण भी हो।

कथा आयोजक श्रद्धेय गिरिराज एवं मित्रमंडल, तथा शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे एलएन ग्रुप, कोटा (राजस्थान) के गोविंद जी, राजेश जी, नवीन और विजय द्वारा यह दिव्य श्रीमद्भागवत कथा आयोजित की जा रही है। मां गंगा तट पर यह पावन आयोजन न केवल आध्यात्मिक आनंद का संचार कर रहा है।

एनएचएआई निर्देशों के खिलाफ वाराणसी रिंग रोड फेज-2 पर भारी वाहनों की आवाजाही से बढ़ा खतरा

मंत्र भारत संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी रिंग रोड फेज-2, जिसे एनएच-2 से जोड़ा गया है, क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाने और शहर के भीतर दबाव कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आधिकारिक घोषणा के विपरीत उठाए गए कदमों ने इस परियोजना को विवाद और खतरे के घेरे में ला दिया है।

एनएच-2 से जुड़ने वाला वाराणसी रिंग रोड फेज-2 शुरुआती चरण में केवल हल्के यातायात (कार, जीप और वैन) के लिए खोला गया था।14 अगस्त 2025 तक इस खंड पर बैरियर और सुरक्षा गार्ड मौजूद रहे ताकि केवल हल्के वाहनों की ही आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

हालाँकि, 15 अगस्त 2025 से स्थिति बदल गई। बैरियर और सुरक्षा गार्ड हटा दिए गए, और इस मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन शुरू हो गया। यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक घोषणा के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि यह खंड केवल हल्के यातायात के लिए खुला रहेगा। हमारी ओर से NHAI को इस विषय पर लिखित सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नहीं हुई है। यह स्थिति सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत चिंताजनक है।

रिंग रोड फेज-2 का बड़ा हिस्सा अभी अधूरा है और कई स्थानों पर दोनों दिशाओं का यातायात एक ही मार्ग पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त, एनएच-19 से जुड़ने वाला चौराहा अभी भी निर्माणाधीन है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में गंगा नदी पर एक तरफ के पुल का निर्माण हो गया है, जबकि दूसरी दिशा के पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और रिंग रोड पूरी तरह से चालू नहीं है, प्राधिकरण ने पुल पर हल्के वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी है।

संबंधित प्राधिकरण को तत्काल भारी वाहनों की आवाजाही की ओर ध्यान देना चाहिए, यह बड़े हादसे का कारण हो सकता है। वाराणसी रिंग रोड फेज-2 केवल एक परियोजना नहीं है, बल्कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तत्काल हस्तक्षेप और उचित कदम उठाना आवश्यक है।

सातविक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 19 सितंबर को खुलेगा

मंत्र भारत संवाददाता

वाराणसी। सातविक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपना बोली/प्रस्ताव शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को खोलेगी। इक्विटी शेयरों के कुल ऑफर का आकार 9000 मिलियन रुपये ड900 करोड़ रूपये तक है, जिसमें 7000 मिलियन रुपये ड700 करोड़ रुपये तक का एक नया निर्गम और बिक्री करने वाले शेयरधारकों द्वारा 2, 000 मिलियन रुपये ड200 करोड़ रुपये तक का ऑफर फॉर सेल ('ओएफएस' और नए निर्गम के साथ, 'ऑफर का आकार') शामिल है। एंकर निवेशक बोली लगाने की तारीख गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 होगी। बोली/ऑफर शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगा और मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को बंद होगा।

ऑफर का प्राइस बैंड 442 रुपये से 465 रूपये प्रति इक्विटी शेयर तय कयिा गया है (पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण वाले हिस्से में बोली लगाने पर प्रति इक्विटी शेयर पर 44 रूपये की छूट दी जा रही है)।

न्यूनतम 32 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 32 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है। कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया कर्जों के पूर्व-भुगतान या निर्धारित पुनर्भुगतान, पूर्ण या आंशिक रूप से, हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सातविक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में, ऋण या इक्विटी के रूप में, पुनर्भुगतान/पूर्व-भुगतान के लिए निवेश, पूर्ण या आंशिक रूप से, हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सातविक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में, राष्ट्रीय राजमार्ग - 16, चमाखंडी, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, गोपालपुर, गंजम - 761 020, ओडिशा में 4 जीडब्ल्यू सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है।

जिला कारागार में बंदियों के लिए ओपन जिम का उद्घाटन

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के जिला कारागार मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायधीश विरजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा भव्य रूप से पूजा अर्चना के साथ ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। जेल परिसर में स्थापित नवीन ओपन जिम में कैदियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम उपकरणों जैसे ट्रेडमिल, चेस्ट प्रेस मशीन, लेग प्रेस, बैक एक्सटेंशन मशीन आदि का प्रदर्शन किया गया, जो विशेष रूप से कैदियों के स्वास्थ्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए चयनित किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश विरजेंद्र कुमार सिंह ने उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि यह ओपन जिम एक नवाचार है, जिसका उद्देश्य कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में पुनः समायोजन की प्रक्रिया तभी सफल होगी, जब कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर समाज में अपने स्थान को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने कहा, 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास संभव है, और यही सोच आज हम सभी के लिए प्रेरणा बनी है।' जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने अपने भाषण में बताया कि वर्तमान समय में कैदियों का पुनर्वास केवल सजाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी बन चुकी है। विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायाधीश अनुभव कटियार तथा शैलेन्द्र नाथ, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर ने इस पहल को समाज में न्याय व्यवस्था की प्रगतिशील सोच के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि कैदी पुनर्वास केवल दंडात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवेदनशीलता व सकारात्मक सोच के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस ओपन जिम से कैदियों को एक नई उम्मीद मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन को सुधारने की दिशा में प्रोत्साहित होंगे। इस अवसर पर उपस्थित कैदियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई कैदियों ने यह बताया कि बंदी जीवन में शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए यह सुविधा मिलने से आशा व उत्साह की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में जेलर राम सिंह यादव, डिप्टी जेलर मुकेश प्रकाश, महेश सिंह एवं प्रभारी अभिषेक कुमार पाण्डेय तथा अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ,पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय के निर्देश पर

कौशाम्बी। श्री आलोक रंजन प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी भदोही एवं इंद्र भूषण यादव ए एच टीयू प्रभारी के संयुक्त रूप से बाल/किशोर श्रमिकों के चिन्हकन हेतु अभियान चलाया गया औराई क्षेत्र के माधवसिंह , घोसिया एवं लाल नगर स्थित कई दुकानों/प्रतिष्ठानों पर जांच किया गया जिसमें एक भी बाल श्रमिक कार्य करते हुए नहीं पाया गया। इस अवसर पर नियोजकों को बाल श्रम /किशोरश्रम न कराए कराए जाने की हिदायत भी दिया गया तथा हेल्पलाइन नंबर 108, 112, 10 76,नंबर 1930 1098 , 181,के बारे में भी सभी को जागरुक भी किया गया तथा वृक्ष भित्ति मादक पदार्थ, मानव तस्करी, की रोकथाम उन्मूलन अभियान की जानकारी दी गई।

पत्रकारों की सुरक्षा व कल्याण को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सौंपा ज्ञापन!

कौशाम्बी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई कौशांबी ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं।

ज्ञात हो कि मांगों में पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन योजना, पत्रकारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति, पत्रकारों के लिए आवास योजना, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता, तथा पत्रकारिता कार्य में उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी संरक्षण जैसी सुविधाएँ शामिल करने की मांग की गई।

ग्रापीए मंडल अध्यक्ष सतीश गोयल तथा जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र अकेला के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अरशद, लवलेश कुमार, कामता प्रसाद चौरसिया, राकेश दिवाकर,निहाल शुक्ला, लवलेश लोधी, राजेश द्विवेदी, अमरेन्द्र कुमार, चंद्र प्रकाश, आदर्श मिश्रा सहित कई पत्रकार मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश में प्रगति की नई उड़ान फ्लिपकार्ट का विकास और सशक्तिकरण का संकल्प

मंत्र भारत संवाददाता

वाराणसी। उत्तर प्रदेश अपनी जीवंत सांस्कृतिक विरासत, उद्यमशीलता की भावना और तेसे विकसित हो रहे डिजिटल इकोसिस्टम के साथ भारत के ई-कॉमर्स परिदृश्य में एक पॉवरहाउस के रूप में उभर रहा है। यहां पर अनेकों कारीगर, एमएसएमई और किसान राज्य के व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए यह राज्य अवसरों और नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के इस गतिशील विकास में फ्लिपकार्ट की एक अहम भूमिका है। फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश की समावेशी वृद्धि में एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में विक्रेताओं और एमएसएमई को समर्थ बनाने, नौकरियों का सृजन करने, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को विस्तारित करने तथा सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में फ्लिपकार्ट का असर सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के प्रति उसके मजबूत समर्थन में दिखाई देता है। लाखों विक्रेता इस प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में अपने उत्पाद बेच पा रहे हैं, जिससे राज्य के उद्यमियों को अपने व्यवसाय को विस्तार करने का मौका मिल रहा है।

रजनीश कुमार, चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने कहा, 'उत्तर प्रदेश फ्लिपकार्ट की विकास यात्रा का केंद्र है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के मजबूत सहयोग ने हमें लाखों रोजगार सृजित करने, एमएसएमई को सशक्त बनाने और स्थानीय कारीगरों, किसानों एवं ओडीओपी उद्यमियों के उत्पाद पूरे भारत के ग्राहकों को उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया है। फ्लिपकार्ट को उत्तर प्रदेश के फ्लैगशिप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में समर्पित माइक्रोसाइट और ऑन-ग्राउंड वर्कशॉप स्थापित की गई हैं। लखनऊ से वाराणसी और आगरा तक, तथा महाकुंभ मेला 2025 जैसे आयोजनों में प्रदर्शनियों के माध्यम से, हम राज्य में शिल्प की समृद्ध परंपराओं और घरेलू उत्पादों को पूरे भारत के ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। राज्य में अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर और साझेदारियों का विस्तार करते हुए हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हम यहां पर सभी के लिए एक ज्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

इस समृद्ध इकोसिस्टम ने 7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं, जो राज्य के रोजगार परिदृश्य को और मजबूत बनाते हैं।

मोबाइल, एथनिक वियर, फुटवियर, ग्रूमिंग, होम फर्निशिंग और हेल्थकेयर जैसी टॉप-सेलिंग कैटेगरीज उत्तर प्रदेश की उद्यमशील विविधता को दर्शाती हैं। साथ ही, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों से उनका विस्तार प्रदर्शित होता है। एमएसएमई की ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, और सेल्स में 100 प्रतिशत की स्थिर साल-दर-साल वृद्धि से प्रदर्शित होता है कि ई-कॉमर्स किस प्रकार राज्य के छोटे व्यवसायों के लिए अवसरों, विस्तार और आय निर्माण में तेला रहा है।

जिलाधिकारी ने इंस्पायर अवार्ड के तहत् छात्राओं को अवार्ड व प्रमाण-पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

कौशाम्बी। । जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को कार्यालय कक्ष में पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज, केसारी की कक्षा-10 की छात्राओं मोहिनी व शाजिया खान को इंस्पायर अवार्ड 2024-25 के अंतर्गत वैज्ञानिक नवाचार एवं विचार में उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

ज्ञात हो कि प्रधानाचार्य नीरज केशरी ने बताया कि इन छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप 10-10 हजार रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किया गया।

उत्तर मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे
बाल्मीकि चौराहा, नवाब यूसुफरोड, प्रयागराज
जोनल सूचना संख्या
आरआरसी/एनसीआर/एक्ट अप्रेन्टिस 01/2025 दिनांक 16.09.2025

शिक्षुता अधिनियम - 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2025-2026 के लिए विस्तृत जोनल अधिसूचना संख्या आरआरसी/उ.म.रे./एक्ट अप्रेन्टिस 01/2025 दिनांक **16.09.2025** को जारी की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थीगण इस संबंध में विस्तृत जानकारी व फार्म ऑनलाईन भरने हेतु इस कार्यालय की अधिकृत वेबसाईट **www.rrcpryj.org** का अवलोकन कर सकते हैं।

अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ
प्रयागराज

1674/25 (C)

@CPRONCR North central railways cproncrly CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

त्योहार विशेष रेलगाड़ी का संचालन

रेल प्रशासन द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित त्योहार विशेष रेलगाड़ी के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

गाड़ी संख्या 09041/09042 उधना जं.-बलिया-उधना जं. (साप्ताहिक) विशेष गाड़ी विशेष किराया

09041 उधना जं.-बलिया विशेष | 09042 बलिया-उधना जं. विशेष

आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
गुरु.	06:40	उधना जं. ▲	12:45	रवि.
00:08	00:10	ललितपुर	19:38	19:40
02:05	02:15	वी. लक्ष्मीबाई झाँसी	18:15	18:25
03:40	03:42	उरई	16:48	16:50
06:50	06:55	गोविन्दपुरी	14:50	14:55
07:58	08:00	फतेहपुर	13:18	13:20
10:10	10:20	प्रयागराज जं.	11:10	11:20
11:48	11:50	मिर्ज़ापुर	09:00	09:02
12:18	12:20	चुनार जं.	08:15	08:17
20:15	शुक्र.	▼ बलिया	शुक्र.	23:30

उधना जं. से: गाड़ी संख्या 09041, गुरुवार, दिनांक 25 सितंबर 2025 एवं 02, 09 अक्टूबर 2025 बलिया से: गाड़ी संख्या 09042, शुक्रवार, दिनांक 26 सितंबर 2025 एवं 03, 10 अक्टूबर 2025 गाड़ी संरचना: वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-14

नोट: ट्रेन की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 1685/25(ADM)

शुद्धि-सूचना

सर्वधारण का सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र मोहम्मद हम्माद खान के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मो0 हम्माद खान अंकित है जो कि गलत है, जबकि सही नाम मोहम्मद हम्माद खान (MUHAMMAD HAMMAD KHAN) है जो कि आधार कार्ड में भी अंकित है, वास्तव मे उपरोक्त जन्म प्रमाण पत्र के लिखत-पढ़त में मोहम्मद हम्माद खान (MUHAMMAD HAMMAD KHAN) को ही सत्य माना जाए जो कि मेरी निजानकारी मे सत्य व सही हैं।

मो0 अशरफ खान
24/30/12, थॉर्नहिल रोड
सिविल लाइन्स, प्रयागराज उ0प्र0।

शुद्धि-सूचना

सर्वधारण का सूचित किया जाता है कि पलक सिंह (PALAK SINGH) के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिवश पिता का नाम पिन्टू सिंह अंकित है जो कि गलत है, जबकि सही नाम पिन्टू कुमार सिंह (PINTU KUMAR SINGH) है जो कि आधार कार्ड में भी अंकित है, वास्तव मे लिखत-पढ़त में पिन्टू कुमार सिंह (PINTU KUMAR SINGH) को ही सत्य माना जाए जो कि मेरी निजानकारी मे सत्य व सही हैं।

पिन्टू कुमार सिंह
पुत्र अवधेश सिंह
निवासी : नया टोला जहांगीरपुर बिदुपुर वैशाली, बिहार
मो0नं0-7355009396

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज

पता :- विकास भवन, प्रयागराज।

ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक - 1396/ग्रा0अ0वि0/निविदा पत्रावली-04/अनु0सहायक/2025-26 दिनांक : 10-09-2025

महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में ए,बी,सी एवं डी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से *ई-टेण्डरिंग* के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है।।

1. **कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैं :-**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	निर्माण लागत (लाख रु0 में)	बिड सिकुरिटि (इ.एम.डी.) (लाख रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जीएसटी सहित (यदि आवश्यक हो) (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	विधायक निधि	सिविल लाइन्स में सैण्ट मैरिज स्कूल में बच्चों हेतु झूला, टाइल्स/इण्टरलाकिंग एवं दो नग वाटर कूलर सहित सौन्दर्यीकरण का कार्य।	18.03	0.37	3000	3 Month
2	विधायक निधि	राजापुर कब्रिस्तान परिसर में इंटरलाकिंग, वाटर कूलर अधिष्ठापन एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	21.06	0.43	3000	3 Month

2- वेबसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि- 01.10.2025 को दोपहर पहर 12:00 बजे से।
3- ई-निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि/समय- 01.10.2025 को प्रातः 12:00 बजे से।
4- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय- 07.10.2025 को सायं 5:00 बजे से।
5- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय- 08.10.2025 को प्रातः 5:00 बजे से।
6- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया वैब साइट http://etender.up.nic.in पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

(एस0पी0 मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड, प्रयागराज

UP - 237752 दिनांक : 15.09.2025 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दशहरा एवं दुर्गा पूजा की तैयारियों के सम्बंध में बैठक सम्पन्न

पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, पेड़ो की छटाई, स्ट्रीट लाइटों एवं सड़कों की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में दशहरा एवं दुर्गापूजा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों व दुर्गापूजा एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों से सम्बंधित कार्यों को समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों से आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, नालियों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था सहित आदि व्यवस्थायें समय से कराये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु बनाये गये तालाबों की साफ-सफाई कराने के साथ ही स्वच्छ पानी भरवाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने के साथ ही लटके जर्जर तारों की मरम्मत, खराब

ट्रांसफार्मरों को बदलने, रास्तों पर लटकते पेढ़ों की टहनियों की छटाई कराने तथा नगर निगम को स्ट्रीट लाइटो को सही कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकरी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से भ्रमण करके सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने एवं संवेदनशील स्थानों का भी अवश्य भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्बुलेंस एवं डॉक्टरों की टीम की उपलब्धता कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने नगर निगम को छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

उन्होंने सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को भ्रमण कर मेला मार्गों की कमियों को दूर कराये जाने के लिए कहा है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग को साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी गैर परम्परागत कार्य नहीं होगा। फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। यातायात की व्यवस्था, डायवर्जन तथा पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अपराध निरोधक, सिविल डिफेंस तथा अन्य सहयोगी विभाग के लोगो की शिफ्ट वाइस ड्यूटी लगायी जाये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारीगण, एसीपीगण सहित रामलीला एवं दुर्गापूजा कमेटी के पदाधिकारीगणों सहित सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

हिन्दी दिवस पखवाड़ा के अन्तर्गत निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा के अन्तर्गत बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति अन्तर्राष्ट्रीय उत्तराखंड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजौना जसरा-प्रयागराज में संस्था द्वारा हिन्दी भाषा पर आधारित चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्राथमिक व जूनियर स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले दीक्षा यादव, दीपिका विश्वकर्मा, आदर्श पाल, सोनम यादव, प्रीति पाल, सुशांत, रागिनी यादव, सोनाक्षी यादव, आकाश पटेल, रिशू यादव, चंचल पटेल, प्रियांशी शर्मा स्वरा केसरवानी, लाडो यादव, अंशू पटेल अंशिका पटेल, प्रतीक्षा को प्रशस्ति पत्र, मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।यह प्रतियोगिता संस्था के अध्यक्ष विवेक बादल बाजपुरी, संरक्षक पंकज शर्मा, महामंत्री भारतेन्द्र त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में और विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी के संयोजन में आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक श्यामाकांत द्विवेदी ने कहा कि हमारी मातृभाषा हमारा अभिमान है हम सबको उस पर नाज़ होना चाहिए।बुलंदी साहित्यिक संस्था द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सराहनीय योगदान है।इस अवसर पर विद्यालय के भारतेन्द्र त्रिपाठी, सुनील कुमार शुक्ल, इरफ़ान अहमद, नाज़िया सुल्ताना, जितेन्द्र कुमार शर्मा , शिशिर जायसवाल, आशीष कुमार गुप्ता, शरद कुमार, राकेश कुमार, पूनम तिवारी पंकज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने 'स्वच्छता ही सेवा' की दिलाई शपथ

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित लोगों को 'स्वच्छता ही सेवा' की शपथ दिलाई स्वच्छता ही सेवा-2025 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को 'स्वच्छता ही सेवा' की शपथ दिलाई और सभी से स्वच्छता पखवाड़ा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने श्रमदान के माध्यम से घर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा है।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की कार्ययोजना के अनुसार सभी कार्यक्रमों को संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्रा, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारी, एसीपी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

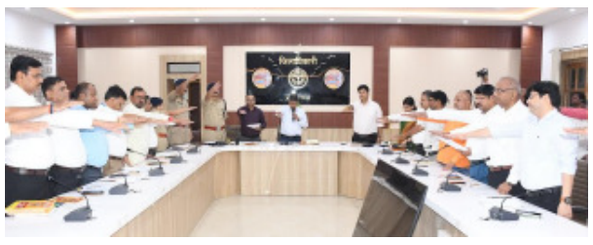

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा अभियान आज से होगा शुभारंभ

सेवा पखवाड़ा के सभी कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगें

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के 75 वें वर्षगाठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ आज 17 सितंबर से होगा भाजपा प्रवक्ता राजेश केसरवानी जानकारी देते बताया कि सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा सुबह 7:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पार्क पर स्वच्छता अभियान चलाकर एवं उन्हें माल्यार्पण कर किया जाएगा

प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने बताया इसके अलावा सुबह बालसन चौराहा के पास स्थित 8: 00 बजे भारद्वाज आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और सुबह 8:20 बजे एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं सुबह 11 बजे जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा और दोपहर 12:00 बजे रक्तदान शिविर का उद्घाटन अन्हा ब्लड बैंक जीएचएस स्कूल सिविल लाइंस में लगाया जाएगा और दोपहर 1:00 बजे दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीडीसी सांस्कृतिक केंद्र अशोक नगर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा जिसमें दिव्यांग जनों को सम्मानित करते हुए उपकरण वितरित किए जाएंगे इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगें।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल सेवा ऑपरेटरों की नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगस्त 2025 के महीने के दौरान उत्तर प्रदेश पूर्व एल एस ए के कानपुर और उन्नाव शहर और प्रयागराज से लखनऊ के मध्यवर्ती राजमार्ग में इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट आयोजित किए थे । इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट को विभिन्न उपयोग क्षेत्रों - जैसे शहरी , हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्र, आदि में वास्तविक दुनिया के मोबाइल प्रदर्शन को आंकने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

भा.दू.वि.प्रा. ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से, कानपुर और उन्नाव शहर में 356.1 किलोमीटर सिटी टेस्ट और 4.8 किलोमीटर वॉक टेस्ट और प्रयागराज से लखनऊ के मध्यवर्ती राजमार्ग में 196.8 किलोमीटर हाईवे ड्राइव टेस्ट 4 अगस्त से 8 अगस्त 2025 के बीच विस्तृत संपन्न किए। ड्राइव टेस्ट के दौरान, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम कार्डों के साथ मोबाइल एडवांस टेस्ट हैंडसेटों का उपयोग करके 2जी, 3जी, 4और 5नेटवर्क पर लाइव डेटा और वॉयस सेशन स्थापित किए गए थे। आईडीटी के निष्कर्षों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का मूल्यांकन किया गया था: क. वॉइस सेवाएं: कॉल सेटअप की सफलता दर, कॉल सेटअप का समय, मीन ओपिनियन स्को का उपयोग करके स्पीच क्वालिटी, कॉल साइलेंस दर, कवरेज-सिग्नल की शक्ति

ख. डेटा सेवाएँ: डेटा थ्रूपुट (डाउनलिंक और अपलिंक दोनों), पैकेट ड्रॉप दर (डाउनलिंक और अपलिंक), वीडियो स्ट्रीमिंग में देरी, लेटेंसी, ज़िटर

कॉल सेटअप सफलता दर: एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में क्रमशः 98.23प्रतिशत, 96.31प्रतिशत, 100प्रतिशत और 98.71प्रतिशत की कॉल सेटअप सफलता दर है।

ड्रॉप कॉल दर: एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में क्रमशः 0.36प्रतिशत, 3.58प्रतिशत, 0.24प्रतिशत और 0.12प्रतिशत की ड्रॉप कॉल दर है।

महाप्रबन्धक नरेश पाल सिंह ने 11 रेल कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

अमर सिंह एवं रजनी कान्त बने माह अगस्त 2025 के सर्वश्रेष्ठ रेलकर्मी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, नरेश पाल सिंह द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, जे.सी.एस. बोरा एवं उत्तर मध्य रेलवे के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में संरक्षा के प्रति किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए झाँसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलों से अगस्त 2025 माह के लिए चयनित कुल 11 रेल कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कृत कर्मचारियों में काली चरण, ट्रैक मेन्टेनर, बांदा, झाँसी मण्डल विक्रान्त बाबू राणा, कीमैन, कोसी कलां, आगरा मण्डल अंशुमान सिंह, प्वाइण्टस मैन, पनकीधाम/प्रयागराज मण्डल श्यामू पटेल, प्वाइण्टसमैन, प्रयागराज छिवकी/ प्रयागराज मण्डल भूरी सिंह, प्वाइण्टसमैन, हेतमपुर/ झाँसी मण्डल धरमपाल राजपूत, वरि. ट्रेन मैनेजर/वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी/ झाँसी मण्डल राधा किशन, वरि. ट्रेन मैनेजर-गुड्स/ईदगाह/ आगरा मण्डल दीपक कुमार सुम्बरूई, लोको पायलट, प्रयागराज छिवकी/ प्रयागराज मण्डल करमेन्द्र कुमार सिंह, सहा. लोको पायलट, प्रयागराज छिवकी/प्रयागराज मण्डल अमर सिंह, लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल रजनी कान्त, सहा. लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल शामिल हैं।

अमर सिंह, लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल एवं रजनी कान्त, सहायक लोको पायलट गुड्स, आगरा कैण्ट/ आगरा मण्डल को संयुक्त रूप से 'माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी' के संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अमर सिंह, लोको पायलट, मालगाड़ी, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल एवं रजनी कान्त, सहायक लोको पायलट, आगरा कैण्ट/ आगरा मण्डल ने 24 जुलाई को गाड़ी सं. घ्छ्उऊ उददे् पर कार्य के दौरान तुगलकाबाद-आगरा कैंट खण्ड में छाता-अझई स्टेशनों के मध्य अझई यार्ड में प्रवेश करते समय अचानक जर्क का अनुभव किया। क्रू द्वारा तुरंत गाड़ी को खड़ा किया तथा जर्क लगने वाले स्थान की जाँच करने पर रेल फ्रैक्चर पाया गया। इसकी सूचना सर्व सम्बंधित को दी। इस प्रकार इनकी सजगता एवं सतर्कता से एक संभावित रेल दुर्घटना को रोका गया।

आईवीएफ की क्या है असली लागत और पैकेज के अलावा आपको क्या-क्या जानना चाहिए?

मंत्र भारत संवाददाता

गोरखपुर। अधिकतर दंपत्ति आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो वह महीनों या सालों की इंतज़ार और सोच-विचार के बाद ही आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो वे आमतौर पर पूछते हैं, वह होता है: 'इसका खर्च कितना होगा?' क्लिनिक्स आमतौर पर एक पैकेज प्राइस बताते हैं, जो शुरुआत में राहत देता है। डॉ. आकृति गुप्ता, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, गोरखपुर बताते हैं कि. जैसे हर दंपत्ति की फर्टिलिटी स्टोरी अलग होती है, वैसे ही खर्च का रास्ता भी हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह पहले से जानना, उन्हें सुरक्षित और फैसलों में सक्षम महसूस कराता है।

लगभग सभी आईवीएफ पैकेजेस के कुछ मूलभूत हिस्से हैं, जैसे - ओवेरियन स्टिमुलेशन, एग रिट्रीवल, फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो ट्रांसफर। ज़्यादातर दंपत्तियों के लिए यह विकल्प बढ़िया होता है और बाद में सफलता प्राप्त हो जाती है।

कभी-कभी, दंपत्तियों को सफ़ल होने का पूरा मौक़ा देने के लिए अतिरिक्त स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, इक्सी (जिसमें एक सिंगल स्पर्म को एग में डाला जाता है), एम्ब्रियो फ्रीज़िंग, या जेनेटिक टेस्टिंग जैसे ट्रीटमेंट्स को उम्र, एग क्वालिटी, या पिछली ट्रीटमेंट हिस्ट्री के आधार पर सुझाया जा सकता है। ये सभी 'छिपे हुए खर्चे' नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकल्प हैं जो चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने जाते हैं ताकि अधिकतम सफ़लता मिल सके।

आईवीएफ केवल एक ट्रीटमेंट्स का सेट नहीं है बल्कि यह एक शारीरिक और भावनात्मक अनुभव है। कुछ लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया उबाऊ हो सकती है, कुछ में एक से ज़्यादा साइकल लग सकते हैं, और इसके लिए पहले से तैयार रहने पर आगे चलकर स्ट्रेस कम हो जाता है। जितना ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है उतना ही ज़रूरी है उपलब्ध कराया गया काउंसलिंग और सपोर्ट, जो इसलिए बनाया गया है ताकि दंपत्तियों को कहीं भी अकेलापन महसूस ना हो।

सबसे सही तरीका वह होता है जिसमें दंपत्तियों को शुरू में ही शिक्षित किया जाए: बेस पैकेज क्या मौज़ूद है, कौन सा दूसरा ट्रीटमेंट सोचा जा सकता है, और कैसे ये सभी फ़ैसले सक्सेस रेट्स से जुड़े हुए हैं। दंपत्तियों को ऐसे क्लिनिक्स ढूढ़ने चाहिए जो पारदर्शी हैं ताकि वो बिना किसी असमंजस के स्पष्ट योजना बना सके।

अंततः आईवीएफ को एक लेन-देन सेवा की तरह कम और देखभाल, विज्ञान और सपोर्ट में निवेश की तरह ज़्यादा देखा जाना चाहिए। क़ीमत केवल पद्धतियों की नहीं बल्कि हर फैसले का मार्गदर्शन करने वाली एक्सपर्टिज, लैब में मौज़ूद तकनीक, और दंपत्तियों को हर जगह संभालने वाली संवेदनशील काउंसलिंग का भी होता है। जब पेशेंट्स इस नज़रिए को समझने लगते हैं तब वो ट्रीटमेंट में अत्यधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कदम रखते हैं।

भाजपाइयों ने केक काट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वे जन्म दिन की दी बधाई

फल एवं मिठाई बांटकर समाज एवं राष्ट्र सेवा का लिया गया संकल्प

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भाजपा मुट्ठीगंज मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मुट्ठीगंज कार्यालय में मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा के नेतृत्व में केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई इस अवसर प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं करोड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत है और उनके जीवन से प्रभावित होकर समाज एवं राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर विकसित भारत निर्माण के लिए काम कर रहा।

इस अवसर पर मिठाई एवं फल वितरण किया गया और राष्ट्र एवं समाज सेवा का संकल्प लिया गया। संचालन सुधांशु त्रिपाठी ने किया। इस अवसर सुनील केसरवानी, अभिषेक जायसवाल, अजय अग्रहरि, आलोक वैश्य, शत्रुघ्न जायसवाल कमलेश केसरवानी, लवकुश केसरवानी, जितेंद्र जायसवाल, विनय जायसवाल, रिन्कू भारतीय विशाल मलिक , दीपक केसरवानी, नीरज केसरवानी, एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

मणिपुर में विकास और शांति की एक नई भोर

मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मैतेयी और कुकी समुदायों के मध्य भड़की हिंसा से अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं तथा 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संघर्ष के आरम्भ से ही भारत के सभी विपक्षी दल निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार पर हमलावर थे, उनका एक ही प्रश्न था कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे ? मणिपुर को लेकर संसद ठप रखी गई। मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ ने मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य नेतागण अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर के हालातों को हथियार बनाते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई अवसरों पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की। विरोधी दलों के भारी दबाव के कारण भाजपा को अपनी ही सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मणिपुर दौरे से सभी को उचित उत्तर दे दिया है किंतु अब विरोधी दलों को इसमें रुचि नहीं रही क्योंकि उनका मणिपुर नैरेटिव फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है। जिस समय भारत में मणिपुर हिंसा पर राजनीति चरम पर थी उस समय यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे केंद्र सरकार ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया था अतः मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने जो देश विरोधी वैश्विक नैरेटिव चलाया था वह भी अब ध्वस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7, 300 करोड़ रुपए से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए 1, 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर यात्रा के दौरान हिंसा पीड़ितों से भेंट करते हुए उन्हें सुरक्षा शांति तथा विकास का भरोसा दिया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भारत की मणि बताते हुए कहा कि मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति बहुत अनिवार्य है। आपसी संवाद और भरोसे से ही विवाद को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मणिपुर के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संवाद, सम्मान और समझौते को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्व गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद दोनो समुदायों के बीच तनाव कम करने के काफी प्रयास किये है जिनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। लगातार चल रहे संवाद के कारण ही कुकी बहुल क्षेत्र से होकर निकलने वाला एनएच दो हाईवे अब पूरी तरह से खुल गया है और जनता व वस्तुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मणिपुर में अभी शांति के लिए कई अहम पड़ाव आने हैं। मैतेयी ओर कुकी समुदाय के बीच कुछ मतभेद अभी भी बरकरार हैं जिनको सुलझाने के प्रयास जारी हैं। इसमें कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की छत के नीचे ही अपने लिए एक अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं फिर भी अब मणिपुर की समस्या का उचित समाधान निकलने की आस जग गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद एक रैली को संबोधित किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी जो मोदी-मोदी के नारे लगा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनसमुदाय मान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से मणिपुर में विकास और शांति लाने वाली एक नयी भोर हुई है।

प्रधानमंत्री का संवाद देश और दिलों को जोड़ता है

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना 75 वां जन्मदिन बुधवार को मनाएंगे। उनकी जीवन यात्रा रचना, सृजन और संघर्ष की त्रिवेणी है। उनके व्यक्तित्व का सबसे खास पक्ष है संचार और संवाद।

भारत जैसे महादेश को संबोधित करना आसान नहीं है। इस विविधता भरे देश में वाक् चातुर्य से भरे विद्वानों, राजनेताओं, प्रवचनकारों और अदीबों की कमी नहीं है। अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने वाले अनेक विद्वानों को हमने सुना और परखा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताएं उनमें विलक्षण हैं। वे हमारे समय के अप्रतिम संचारकर्ता हैं। संचार का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनकी तरफ बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखता हूं, किंतु वे अपनी देहभाषा, भाव-भंगिमा, शब्दावली और वाक् चातुर्य से जो करते हैं, उसमें कमियां ढूंढ पाना मुश्किल है। उनका आत्मविश्वास और शैली तो विलक्षण है ही, वे जो कहते हैं उस बात पर भी सहज विश्वास करने का मन होता है। मोदी सही मायने में संवाद के महारथी हैं। वे जनसभाओं के नायक हैं तो एक्स जैसे नए माध्यमों पर भी उनकी तूती बोलती है। पारंपरिक मंचों से लेकर आधुनिक सोशल मीडिया मंचों पर उनकी धमाकेदार उपस्थिति बताती है संवाद और संचार को वे किस बेहतर अंदाज में समझते हैं।

गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में पले-बढ़े नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो लोगों को सम्मोहित करता है? उनकी राजनीतिक यात्रा भी विवादों से परे नहीं रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिस तरह निशाना बनाकर उनकी छवि मलिन करने के सचेतन प्रयास हुए, वे सारे प्रसंग लोकविमर्श में हैं। बावजूद इसके वे हिंदुस्तानी समाज के नायक बने हुए हैं तो इसके पीछे उनकी संप्रेषण कला और देहभाषा का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कभी सांसद नहीं थे और पहली बार लोकसभा पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के आमचुनावों की याद करें तो देश किस तरह निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। लोग राजनीति और राजनेताओं से उम्मादें छोड़ चुके थे। अन्ना आंदोलन से एक अलग तरह का गुस्सा लोगों के मन में पनप रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है 'मैं देश नहीं झुकने दूंगा।' दूसरी आवाज थी 'अच्छे दिन आने वाले हैं।' ये दो आवाजें थीं नरेंद्र मोदी की, जो देश को एक विकल्प देने के लिए मैदान में थे।

राजनीति में आश्वासनपरक आवाजों का बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि राजनीति तो सपनों और आश्वासनों के आधार पर ही की जाती है। किंतु नरेंद्र मोदी ने इस दौर में जो कुछ कहा उसे देश ने बहुत ध्यान से सुना। उनका दल लंबे समय से सत्ता से बाहर था और वे अपने दल की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जा चुके थे। जाहिर है अवसाद और निराशा से भरी जनता को एक अवसर था परख करने का। मोदी इस अवसर का लाभ उठाते हैं और जनता के मन में भरोसा जगाने का प्रयास करते हैं। वे लगातार अपनी सभाओं में कहते हैं कि वे ही इस देश को उसके संकटों से उबार सकने की क्षमता से लैस हैं। जनता मुग्ध होकर उनके भाषणों को सुनती है। अपनी अप्रतिम संवादकला से वे लोगों में यह भरोसा जगाने में सफल हो जाते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं।

2014 में मोदी सत्ता में आते हैं और संचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम को साधते हैं। वे आकाशवाणी पर 'मन की बात' के माध्यम से लोगों से संवाद का अवसर चुनते हैं। यानि उनका संवाद अवसर और चुनाव केंद्रित नहीं है, निरंतर है। उनमें एक सातत्य है। बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, लोकजागरण के लिए। वे मन की बात को राजनीतिक विमर्शों के बजाए लोकविमर्शों का केंद्र बनाते हैं। जिसमें जिंदगी की बात है, सफाई की बात है, शिक्षा और परीक्षा की बात है, योग की बात है। मन की बात के माध्यम से वे खुद को एक ऐसे अभिभावक की तरह पेश करने में सफल होते हैं, जिसे देश और देशवासियों की चिंता है। संवाद की यही सफलता है और यही उसका उद्देश्य है। अपने लक्ष्य समूह को निरंतर अपने साथ जोड़े रखना मोदी की संवाद कला की दूसरी सफलता है। करोना संकट में भी हमने देखा कि उनकी अपीलों को किस तरह जनमानस ने स्वीकार किया, चाहे वे करोना वारियर्स के सम्मान में दीप जलाने और थाली बजाने की ही क्यों न हों। यह बातें बताती हैं कि अपने नायक पर देश का भरोसा किस तरह कायम है।

मोदी अपनी देहभाषा से कमाल करते हैं। कई बार चौंकाते भी हैं। देश की गहरी समझ भी इसका बड़ा कारण है, यही कारण है वे देश के जिस हिस्से में होते हैं वहां की स्थानीय बोली, वस्त्रों और प्रतीकों का सचेत इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उनकी पोशाकें, उनका हाफ कुर्ता, जैकेट्स आज एक तरह से स्टाइल स्टेटमेंट है। उनका अनुसरण कर नौजवान आज खद्दर और सूती कपड़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनका समर्पित जीवन और ईमानदारी से उनकी वाणी का भी एक रिश्ता है। जब हम सिर्फ बोलते हैं तो उसका असर अलग होता है। किंतु अगर हम जो बोलते हैं उसमें कृतित्व भी शामिल हो तो बात का असर बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी अपनी असंदिग्ध ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित है। ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपकी वाणी को आपके जीवन का समर्थन है। सिर्फ देश की बात करना और देश के लिए जीना दो बातें हैं। मुझे लगता है जीवन और कर्म में एक रूप होने के नाते मोदी बाकी राजनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर सबको भरोसा है, इसलिए उनकी वाणी पर भी सहज विश्वास आता है। इस तरह उनकी वाणी 'भाषण' न होकर 'हृदय से हृदय के संवाद' में बदल जाती है। लोगों को भरोसा है कि वे हमारी ही बात कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं। मोदी ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि की बात कभी छिपाई नहीं, जब भी उनकी साधारण स्थितियों का मजाक बनाया गया तो उसे भी उन्होंने एक सफल अभियान में बदल दिया। 'चाय पर चर्चा' का कार्यक्रम किस तरह बना, उसके संदर्भ हम सबके ध्यान में हैं। नरेंद्र मोदी सही मायने में सामान्य जनों में भरोसा जगाते हैं कि अगर संकल्प हों, इच्छाशक्ति हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यह एक बात लोगों को उनसे कनेक्ट करती है। अनेक राजनेता हैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं। किंतु उनका या तो अपनी जड़ों से उनका रिश्ता टूट गया है या वे उन विथिकाओं को याद नहीं करना चाहते। जबकि नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूलते वे हमेशा उसे याद करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। यही कारण है उनका कनेक्ट सीधा जनता से बनता है। वे प्रधानमंत्री होकर भी अपने से नजर आते हैं। संचार, संवाद और पोजिशिनिंग की यह कला उनमें सहज है। बिना जतन के भी वे इन सबको साधते हैं और साधते रहेंगें क्योंकि आसमान पर होकर भी माटी की सोंधी महक उन्हें जड़ों से जोड़े रखती है। इसलिए उनका संवाद दिलों को जोड़ता है, देश को भी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके कुछेक प्रावधानों में विधिसम्मत और तर्कसंगत संशोधन किया है या फिर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस ताजातरीन फैसले से वे आशंकाएं दूर हो जाएंगी, जो इस नए कानून को लेकर इससे पहले जताई जा रही थीं। चूंकि कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे मान लिया है। यह एक शुभ लक्षण है।

बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए संशोधन महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें संविधान की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसके परिवर्तित मायने राष्ट्रीय एकता के लिहाज से अहम हैं।

पहला, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, बताया गया है। हालांकि यह रोक तभी तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकारें इसके लिए अलग से नियम नहीं बना देतीं। चूंकि यह शर्त मनमानी हो सकती थी, इसलिए अदालत ने इसे स्थगित कर दिया है। समझा जाता है कि वक्फ करने के लिए न्यूनतम 5 बरसों तक इस्लाम का अनुयायी होने के प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी, जब तक राज्य सरकारें इसके सत्यापन के लिए नियम नहीं बना लेती। चूंकि देश में धर्म व्यक्तिगत मामला है और यह जरूरी नहीं कि कोई नागरिक अपनी धार्मिक पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन करे। इसलिए यह तय करना कि कोई किसी धर्म को कब से मान रहा है, बेहद जटिल है। राज्य सरकारों से उम्मीद है कि इस बारे में नियम बनाते समय वे सभी पहलुओं का ध्यान रखेंगी और ज्यादा संवेदनशीलता बरतेंगी।

दूसरा, कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि जिला कलेक्टर को यह फैसला देने का अधिकार नहीं है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट अंतिम निर्णय न कर ले। इससे कलेक्टर की शक्ति सीमित हुई है और मनमानी पर रोक लगी है। यह एक अहम संशोधन है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संपत्ति जांच के प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामित अधिकारी की आंशिक रूप से रिपोर्ट के आधार

पर ही किसी प्रॉपर्टी को गैर-वक्फ नहीं माना जा सकता। समझा जाता है कि अदालत ने संपत्ति अधिकार तय करने की ताकत जिलाधिकारी को देने को संविधान में की गई व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ माना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि लोकतंत्र के तीनों अहम अंगों- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। एक पक्ष की ओर पलड़े का थोड़ा भी झुकाव व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ देगा।

तीसरा, वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या और गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा में संशोधन भी कुछ हद तक सुरक्षित की गई है, लेकिन कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर स्थगन लगाया है। लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी सरकार अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह के कानून लाएगी व उसका अनुपालन का निर्णय करेगी।

चतुर्थ, कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को शक्ति के 'मनमाने' प्रयोग को रोकने के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और बुजुर्गों का धर्म पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के कई बिंदुओं पर विपक्ष को गहरी आपत्ति थी। इसे लेकर दोनों सदनों में और सड़क पर भी काफी हंगामा हुआ। इस मामले की गंभीरता और उसके असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिम्मेदारी भरा है।

यूँ तो इस बाबत दायर याचिका में पूरे कानून को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे नहीं माना। इस तरह के कदम बेहद दुर्लभ मामलों में उठाए जाते है और इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। देखा जाए तो इस मायने में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया, और यह भी ध्यान रखा कि विधायिका के साथ सीमाओं का अतिक्रमण न हो। इसलिए उसने समझदारी पूर्वक बीच का रास्ता निकाला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में बेहद संतुलित नज़रिया अपनाया है।

सच कहा जाए तो कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून में संतुलित नज़रिया को अधिक न्यायसंगत और संवैधानिक बनाने की दिशा में संकेत देता है। साथ ही इसके मार्फ़त सरकारी शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित कुछ नियम और प्रावधान तभी तक लागू नहीं होंगे, जब तक इस बारे में अधिक स्पष्ट नियम और निर्देश नहीं बन जाते।

इस तरह से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। ऐसा करके उसने एक ओर जहां संतुलित नजरिया अपनाते हुए शक्ति का संतुलन बिठाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून पर फैसला देते हुए उसने अतिरिक्त संवेदनशीलता की जरूरत भी समझी है। यही वजह है कि अपेक्षाकृत विवादास्पद मामलों में उसका एक और जिम्मेदारी भरा निर्णय सामने आया है, जिससे देश-प्रदेश ने राहत की सांस ली है।

नेपाल के जेन-जेड के साथ फिर बड़ा धोखा हो गया क्या?

नेपाल और नेपाल जैसे कई लोकतांत्रिक देशों में युवाओं के साथ लगातार छल होता रहा है। कई देशों में युवाओं ने सड़क पर उतर कर अपने साथ किए गए धोखे का जवाब भी देने की कोशिश की लेकिन विडंबना देखिए कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी युवाओं के हाथ अंत में खाली ही रह जाते हैं। नेपाल के ज्यादातर युवा आंदोलनकारी अपने आपको अब इसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं।

हिंसा या हिंसक आंदोलन को किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह भी अपने आप में एक तथ्य है कि नेपाल में जिस तेजी से अचानक जेन-जेड युवा आक्रमक अंदाज में सड़कों पर उतर गए, उसमें किसी विदेशी ताकत के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी यह स्थापित तथ्य है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में गड़बड़ी तभी करा पाता है,जब उस देश में लोगों का असंतोष चरम पर पहुंच जाता है। नेपाल में उसी तरह के हालात बन गए थे,इससे भला कौन इनकार कर सकता है।

नेपाल की सड़कों पर उतर कर हंगामा करने वाले जेन-जेड प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, राजनीतिक अव्यवस्था एवं भाई-भतीजावाद को खत्म करने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध को हटाना था। लेकिन सड़कों पर उतरे युवा एक सुर में कह रहे थे कि उन्होंने अपने देश में बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन किया है।

नेपाली युवा एक सुर में सत्ता सुख भोग रहे या सत्ता सुख भोग चुके नेताओं को पूरी तरह से हटा देना चाहते थे। लेकिन क्या वाकई उनकी यह मंशा पूरी हुई ? नेपाल में शांति स्थापित करने के नाम पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता सौंप दी गई है।

आपको बता दें कि, 7 जून 1952 को जन्मी सुशीला कार्की, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही, वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। लेकिन बुजुर्ग नेताओं से त्रस्त नेपाल को शांति स्थापित करने के नाम पर 73 वर्ष की एक नई प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या 73 वर्ष की सुशीला कार्की नेपाल के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों के साथ न्याय कर पाएंगी? उनकी परेशानियों और दिक्कतों को समझ कर, दूर कर पाएंगी ? अगर सिर्फ चुनाव करा देना ही समस्या का समाधान होता तो नेपाली युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता? यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति (भले ही वह किसी भी पद पर रहा हो) सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा रहा हो वो उस व्यवस्था में कभी भी बड़ा और व्यापक बदलाव नहीं ला सकता है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े बवाल के बावजूद बुजुर्ग नेताओं के रवैए में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब आज भी अपने-अपने राजनीतिक दलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अभी से इन्होंने बदलाव का विरोध करना शुरू कर दिया है।

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शुक्रवार शाम को सुशीला कार्की को शीतल निवास में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद से सभी पिछली सरकारें अनुच्छेद 76 के तहत गठित हुई थीं लेकिन पहली बार अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि अंतरिम प्रधानमंत्री को छह महीने के भीतर देश में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। गौर कीजिएगा, सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह का नेपाल की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और सांसदों ने बहिष्कार किया। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने पर भी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल शपथ ग्रहण समरोह में नहीं पहुंचे। ध्यान रहे, घिमिरे केपी ओली की पार्टी के सांसद हैं जबकि दहल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचण्ड की पार्टी के नेता है। नेपाल के राजनीतिक दल या दूसरे शब्दों में कहें तो नेपाल के बुजुर्ग नेता संसद भंग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर 6 महीने के भीतर जब भी चुनाव होंगे तो यही राजनीतिक दल और यही नेता तो लड़ेंगे। चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो यही बुजुर्ग नेता आपस में जोड़-तोड़ कर सरकार बनाएंगे और मिल कर नेपाल की जनता खासकर नेपाली जेन-जेड के सपनों को रौंदते रहेंगे। नेपाल के जेन-जेड ने नेताओं की संगठित लूट को फिर से देखने के लिए तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं ही किया था।

नेपाल से सीखा सबक! भारत में आंदोलनों का अध्ययन कर भविष्य की रणनीति बनाएगी मोदी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह निर्देश दिया है कि 1974 से अब तक देश में हुए प्रमुख आंदोलनों का गहन अध्ययन किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि किन कारणों से बड़े पैमाने पर असंतोष पनपता है और भविष्य में 'स्वार्थी तत्वों' द्वारा आंदोलन की आड़ में अशांति फैलाने की संभावनाओं को रोका जा सके।

देखा जाये तो 1974 का वर्ष भारतीय राजनीति में विशेष महत्व रखता है। यह वही दौर था जब जेपी आंदोलन ने बिहार से उठकर राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया और अंततः 1975 में आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी। उसके बाद से छात्र आंदोलनों, किसान आंदोलनों, आरक्षण विरोधी और समर्थनकारी आंदोलनों, अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन, शाहीन बाग का नागरिकता संशोधन कानून विरोध और हालिया किसान आंदोलन, ये सभी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के निर्णायक पड़ाव रहे हैं।

देखा जाये तो अमित शाह का यह कदम मात्र अतीत की घटनाओं की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि आंदोलन की प्रकृति, उनकी पृष्ठभूमि, उनसे हुई सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल और उनके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को समझना है। सवाल यह है कि कौन-से आंदोलन वास्तविक जनआकांक्षाओं के प्रतिनिधि थे? किन आंदोलनों को संगठित समूहों या बाहरी ताकतों ने दिशा दी? आंदोलन कब लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बने और कब हिंसा या अराजकता में बदल गए? इन सवालों का उत्तर ढूंढ़ना इस अध्ययन का मूल मकसद प्रतीत होता है।

मोदी सरकार की इस कवायद के वर्तमान संदर्भ में मायने समझें तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि आज भारत ऐसे समय में है जब सूचना और संचार तकनीक ने आंदोलन करने की शैली को बदल दिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए आंदोलन बहुत तेज़ी से आकार ले सकते हैं। साथ ही स्थानीय असंतोष देखते-देखते राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा, विपक्षी दल और अंतरराष्ट्रीय मंच भी आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने में सक्रिय रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय की इस पहल के कई मायने हैं।

जैसे- सरकार आंदोलन के पीछे छिपी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझकर बेहतर नीतियाँ बना सकेगी। साथ ही अगर किसी आंदोलन को विदेशी या विध्वंसकारी ताकतें भड़काती हैं, तो उनकी पहचान करना आसान होगा। इसके अलावा, मोदी सरकार यह भी दर्शाना चाहती है कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों और अनुशासन के बीच संतुलन कायम रखने के पक्ष में है। मोदी सरकार का यह निर्णय यह भी बताता है कि केंद्र सरकार आंदोलनों की राजनीति को सिर्फ तात्कालिक चुनौती नहीं मानती, बल्कि दीर्घकालिक नीति-चिंतन के विषय के रूप में देख रही है।

हालाँकि, सरकार के इस फैसले की आलोचनाएँ होनी भी संभव हैं। विपक्ष इसे 'आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश' कह सकता है। देखा जाये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन असहमति जताने का वैध साधन हैं, ऐसे में उनका अध्ययन करने को कुछ लोग नागरिक अधिकारों पर अंकुश की तैयारी मान सकते हैं। वैसे अमित शाह का यह निर्णय केवल अतीत को खंगालने का नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को दिशा देने का प्रयास है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार आंदोलन की राजनीति को हल्के में नहीं ले रही और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा कि यह अध्ययन संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है या फिर केवल आंदोलनों को 'स्वार्थी तत्वों' की कारस्तानी करार देने तक सीमित रह जाता है।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेपाल में जेन-ज़ेड युवाओं के आंदोलन ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से असंतोष प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतरने से हिचकती नहीं। इसके अलावा, दक्षिण एशिया के अन्य देशों– जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हाल में जन आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में अरब स्प्रिंग के उदाहरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता की असंतुष्टि, यदि समय रहते संभाली नहीं जाए, तो वह तख़्तापलट या शासन परिवर्तन का कारण बन सकती है।

जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न प्रगति सुधारने के निर्देश-जिलाधिकारी

सैम बच्चों की पहचान व पोषण पोटली उपलब्ध कराने के निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक कलेक्टेड्ट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि जिन इंडिकेटर पर प्रगति खराब है उनमें प्रगति कर सुधार लाएं अन्यथा कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने जनपद की उज्ज्वल आजीविका एवं रानी लक्ष्मी बाई स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार पोषण पोटली प्रोटीनला का आगनबाड़ी केन्द्रों व लाभार्थियों तक उपलब्ध कराया जायेगा। सैम मैम बच्चों की पहचान करने हेतु आगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आशा की संयुक्त टीम बनाकर पहचान करने का निर्देश दिया। डीएम ने डीपीआरओ संजय मिश्र को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत निधि से जनपद के सभी आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बच्चों के वजन व लम्बाई हेतु स्केल मशीन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सम्भव अभियान के कुशल संचालन हेतु सीडीपीओ, चिकित्सा प्रभारी डाटा फीडिंग को सुनिश्चित कराये।

प्रधानमंत्री जी विजन सुपोषण भारत/कुपोषण मुक्त भारत पर आधारित आठवां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 17 सितम्बर को चित्रांगना लान ज्ञानपुर में आयोजित किया जायेगा। जिसमें मोटापा निवारण चीनी व तेल के उपभोग में कमी, पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ मॉ के नाम, शिशु एवं बाल आधारित कथाएं, पुरूष सहभागिता आदि थीम पर जनसंवेदीकरण गतिविधियॉ आदि आयोजित की जायेगी।

उन्होंने पोषण पुर्नावास केन्द्र में सैम बच्चों को प्रभावी प्रयास कर भर्ती कराये जाने हेतु निर्देश दिये। आगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि जो केन्द्र फिनिसिंग स्तर पर है उन्हें जल्द ही पूर्ण कराकर हस्तगत करा लिया जाये। साथ ही साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ समन्वय बैठक कर महिला व बालकों के हित में धरातली स्तर पर अधिक प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। पीएफएमएस पोर्टल पर आगनबाड़ी कार्यकत्री सहायिका का आधार व मोबाइल सत्यापन के कार्यो पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ बन्दन योजना के अवशेष कार्यो को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु डीएम ने निर्देश दिये। ।

मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माह जुलाई से सितम्बर 2025 में सम्भव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सम्भव अभियान का मुख्य उद्देश्य सम्भव अभियान का मुख्य उद्देश्य सैम श्रेणी के शिशुओ की समयवद्ध पहचान, समुचित उपचार एवं पोषण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाना तथा 0 से 6 माह आयु के शिशुओ में कुपोषण से बचाव हेतु छः माह सात बार रणनीति को स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग से आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा परस्पर समन्वय से छः माह में सात बार गृह भेट कर अल्प वजन के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उनका पोषण प्रबन्धन सुनिश्चित कराया जाना निर्धारित किया गया है। सम्भव अभियान 2025 का मासिक थीम, जुलाई माह- मातृ पोषण, अगस्त माह-06 माह से छोटे बच्चो शिशुओ का विशेष ध्यान, सितम्बर माह-उपरी आहार प्रोसाहन एवं पोषण माह चलाया जा रहा है।

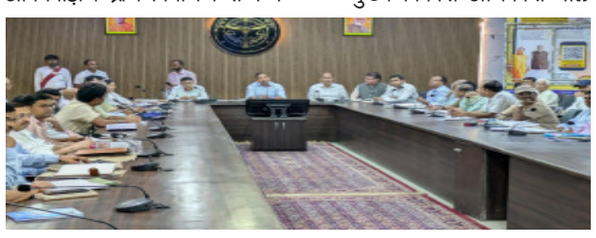

पुलिस मुठभेड़ में 10000 का सातिर इनामिया गिरफ्तार

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में वांछित पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ?10, 000/- पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश उपाध्याय उर्फ धम्मू पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी बनकट ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र 25 वर्ष को ग्राम सिंहपुर नाहर पुलिया से लगभग 200 मीटर दाहिने मार्ग पर बहद थाना ज्ञानपुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना ज्ञानपुर पर आवेदक राजमन पुत्र श्री रामकिशुन यादव निवासी ग्राम कंसापुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही का दिनांक 10.09.2025 की रात्रि लगभग दो बजे मोटरसाइकिल (गाड़ी) एवं मोबाइल चोरी हो गयी। उक्त घटना के संबंध में थाना भदोही पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग

पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई। उपरोक्त घटना के अलावा अभियुक्त द्वारा कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त के अन्य अपराधों में संलिप्तता की जानकारी की जा रही है। दिनांक 28.07.2021 को भदोही पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आकाश उपाध्याय उर्फ धर्म उपाध्याय पुत्र राजकुमार उम्र 18 करीब वर्ष निवासी बनकट (वेदपुर) थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही को उसके साथी डब्बू गौतम के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के बताए गए स्थान से अन्तर्गत धारा 41, 411, 413, 414 छ्प्ण व सम्बन्धित मु0अ0स0 159/2021 धारा 379 छ्प्ण में कुल चार अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई थी।

दिनांक 06.03.2021 की रात्रि में आवेदक विकाश चन्द्र पाण्डेय ए/0 राजपति पाण्डेय, वेदपुर ज्ञानपुर भदोही के घर से चैन/लाकेट एवं 4000/ रूपया व एक मोवाइल चोरी के संबंध में अभियुक्त आकाश उपाध्याय उर्फ धम्मू पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी बनकट ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया था।

दिनांक 16.03.2021 को थाना ज्ञानपुर पर प्रकाश सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह निवासी ग्राम सनकडीह (अजयपुर) थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के बैग से 06 अदद मोबाइल फोन व दो हजार रुपया करिब 11.00 बजे रात्रि को अभियुक्त आकाश उपाध्याय उर्फ धम्मू पुत्र राजकुमार उपाध्याय उर्फ पकौड़ी निवासी ग्राम वनकट थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा चोरी किया गया था।

दिनांक 18/19.8.20को अभियुक्त आकाश कुमार उपाध्याय उर्फ धम्मु पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी बनकट जमीने छनौरा थाना ज्ञानपुर जिला भदोही द्वारा अपने पड़ोसी के छत पर चढ़कर रात्रि 02 बजें कमरे में रखा हुआ पीतल का परात, छोटा गैस सिलेन्डर और एक बोरी गेहूं चोरी किया गया।

जिला वृक्षारोपण, पर्यावरण, गंगा समिति की बैठक डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न

सम्बन्धित विभाग पौधरोपण शत-प्रतिशत जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण-जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति व गंगा समिति, पर्यावरण के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्टेड्ट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि जनपद का लक्ष्य 13, 41700 लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है। सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों के स्थलों का जीओ टैगिंग शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। सभी पौधों की सुरक्षा सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा। जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, तभी हम लोग भी सुरक्षित होंगे, जो पेड़ लगाये गये है उन पेड़ों का बचाव का प्रयास हम करेंगे संकल्प लें। रोपित किए गए पौधों के रखरखाव एवं अन्य बिंदुओं पर बल दिया गया।

जिला पर्यावरण समिति के अंतर्गत जनपद में उत्पन्न हो रहे गीला कचरा के उपचार हेतु उपलब्ध वेट कंपोस्टिंग पिट की कार्यात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। जनपद में उत्पन्न हो रहे प्लास्टिक अपशिष्टों को रिसायकल एवं प्रबन्धन (सड़क निर्माण, ऊर्जा निर्माण इत्यादि में) हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट ट्रांसफर स्टेशन, डम्पिंग साईट क्षमता एवं कार्यात्मक स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट पर बल दिया गया। जनपद में उत्पन्न हो रहे कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के उचित निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। जनपद में उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन (वेस्ट टू कम्पोस्ट एवं वेस्ट टू एनर्जी) हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के फण्टलाईन स्टाफ के कार्यात्मक क्षमता की अभिवृद्धि हेतु किये जा रहे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। जनपद में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

सुरियावा बाईपास पर घनश्याम कोल्ड स्टोरेज के सामने खुला नाला स्थानीय लोगों के लिए परेशानी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। सुरियावा बाईपास पर घनश्याम कोल्ड स्टोरेज के सामने खुला नाला स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नाले से फैल रही गंदगी और दुर्गंध से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

नाले की वजह से राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुले नाले में जमा गंदा पानी मच्छरों और कीड़ों के पनपने का कारण बन रहा है। इससे आसपास के क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

स्थानीय निवासियों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि नाले का उचित निर्माण किया जाए। साथ ही इसकी नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। इससे क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहेगी और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।इस अवसर पर दिलीप सिंह, विकास, निहाल सिंह, चंदन, पवन सहित कई लोगों ने मांग की।

बेरासपुर में चकबंदी प्रकिया के तहत किसानों के अंश निर्धारण की गई रैण्डम चेकिंग

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। गोपीगंज क्षेत्र के बेरासपुर में स्थित बेरासनाथ शिव मंदिर पर चकबंदी अधिकारी और ग्रामीणों की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के लोगों को चकबंदी प्रक्रिया और उसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया और चकबंदी लेखपाल द्वारा किसानों की जमीन के रकबे का जो अंश निर्धारण किया गया है, उसकी रैण्डम चेकिंग भी की।

बैठक में सहायक चकबंदी अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार बढ़ने के साथ ही अक्सर जमीनों का बटवारा भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई जमीन और पैतृक जमीन अलग-अलग जगहों पर होती है। जिसके वजह से किसानों को खेती करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अधिक समय होने के साथ ही गांवों में भूमि विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण समेत कई शिकायतों की संख्या अधिक होने लगती है।

जिसके कारण सरकार एक निश्चित समय के बाद चकबंदी कराती है। चकबंदी के तहत इधर-उधर बिखरे हुए खेतों को एक जगह किया जाता है, जिससे किसान आसानी से आधुनिक खेती कर सकते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी ने किसानों से बताया कि किसी भी तरह की जो समस्या हो उसे चकबंदी लेखपाल से बताकर उसका समाधान कर ले। कहीं किसी के बहकावे या अफवाह में न आये। चकबंदी कि प्रकिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है और इसे ऐसे ही पूर्ण भी कराया जायेगा। कहा कि वरासत और नामांतरण की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा।

मालूम हो बेरासपुर ग्रामसभा में चकबंदी की प्रकिया शुरू है। ग्रामसभा में चकबंदी लेखपाल बीते कई माह से ग्रामसभा के सभी रकबा को चिन्हित करते हुए सम्बंधित कास्तकारों से बातचीत करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे रहे है. और सभी के रकबा में अंश निर्धारण भी कर दिये है। जिससे की भविष्य में कहीं कोई दिक्कत न हो। हालांकि किसी बात की आपत्ति के लिए सभी को मौका रहेगा। बैठक में सहायक चकबंदी अधिकारी वैभव श्रीवास्तब, ग्राम प्रधान मिथलेश कुमार, कानूनगो अंगदराम, लेखपाल आदर्श दूबे समेत भारी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे।

दशहरा होगा और भी खास - 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ट्रेलर लॉन्च

जित मुम्बई। लव, लाफ्टर और फैमिली मैजिक की एक भव्य दावत। सेटिंग? एकदम बिग फैट इंडियन शादी! जहां रोमांस है, कॉमेडी है और त्योहारों वाली चमक-दमक भी। ये फिल्म पुराने जमाने वाले फैमिली एंटरटेनर का असली मज़ा वापस लाने का वादा करती है।

स्टेलर कास्ट - वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल - मतलब मस्ती और इमोशन्स का रोलरकोस्टर राइड पक्का।

डायरेक्टर शशांक खेतान अपनी स्पेशलिटी - इमोशन और ह्यूमर - के साथ लौटे हैं।

करण जौहर बोले, 'फैमिली एंटरटेनर हमारी स्टोरीटेलिंग का दिल है। ये फिल्म साथपन और खुशी का सबसे बड़ा जश्न है।'

शशांक खेतान : 'ये फिल्म थिएटर में फैमिली को साथ लाने के लिए बनाई गई है। इसमें रिश्ते हैं, म्यूज़िक है और वो नॉस्टैल्जिया है जो दिल छू जाए।'

प्रोड्यूसर्स - हीरू यश जौहर, करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता और शशांक खेतान - लाए हैं ये सबसे स्पेशल रिलीज़।

कैलेंडर मार्क कर लो - इस दशहरा, 2 अक्टूबर 2025 को, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ सिनेमाघरों में होगा प्यार और फैमिली का सबसे ग्रैंड सेलिब्रेशन!

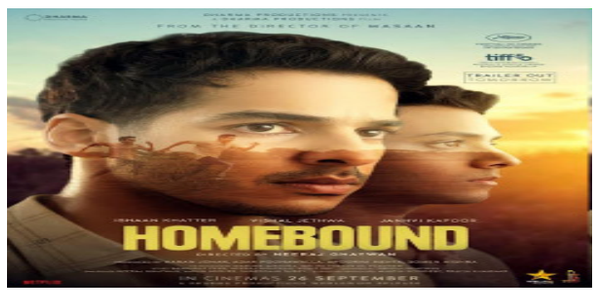

सनातनियों के माथे पर लगे गौहत्या के कंलक को दूर करना शंकराचार्य का दायित्व

जिसने खुद को सनातन परमात्मा से जोड़ लिया वही सनातनी है

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। अररिया जिले के फारबिसगंज में आदर्श गोयल जी आवास पर रात्रि विश्राम के पश्चात आज तय कार्यक्रम के अनुसार परमाराध्य परमधर्माधीश ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानंदः सरस्वती जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीश्री 1008 लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुच कर सभी देवी देवताओं का दर्शन करके शिव जी अभिषेक व आरती किया।मन्दिर परिसर में पहुचने पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पवन अग्रवाल ने सहयोगियों के साथ पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का स्वागत, अभिनंदन व वंदन किया।जिसके अनंतर वहीं पर गौमतदाता सभा का आयोजन किया गया।

गौमतदाता सभा को सम्बोधित करते हुए परमधर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि सदा रहने वाला ही सनातनधर्म है जो भूत, वर्तमान और भविष्य में भी रहने वाला है और जिसने सनातन परमात्मा से अपने आपको जोड लिया वही सनातनधर्मी है और यही आपका परिचय है।हिन्दू वो जो हिंसा से दुखी हो जाता है, जीवन धारण करने के लिए कुछ अनिवार्य हिंसा हमें करनी ही पडती है, उसके प्रायश्चित के लिए हर गृहस्थ रोज क्रमशः देवयज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और बलि वैश्वदेव पंचमहायज्ञ करके अनिवार्य हिंसा की प्रायश्चित करता है।इसका मतलब हम हिन्दू रोज प्रायश्चित करते हैं और साथ ही हम गौरक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये निर्धारित कर रखा है कि हमें किसी भी हालत में गौ हत्या नही करना है।वेदों में गाय को अवध्या कहा गया है, पुराणों में अनेकानेक आख्यान है जिसमें बताया गया

कि गाय को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे डाला था।पर आज डालर कमाने के लिए हम अपनी गाय को काट कर बेच दिया है, हम को आज खडे होकर गाय को हर कीमत पर बचाना ही होगा।देश की आजादी के समय से हमसब नेताओं को वोट व अपना समर्थन देकर गौहत्या के पाप के भागीदार बन रहे हैं।

श्रीशंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि आपके माथे गौहत्या का पाप चढा है इसलिए आप दुखी हो, गुरु होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी सनातनी प्रजा के माथे पर से गौहत्या के कलंक उतार दें।आप अपने असली ताकत को पहचानिए और गौहत्या कराने वाले दलों व नेताओं को वोट देना बन्द करिए।जो गौ प्रत्याशी शपथपूर्वक गौसेवा की उद्घोषणा करे उसी की अपना वोट दीजिए।जो नेतागण हमारा वोट लेकर हमारी माता गाय को कटवाते हो वो हमें कदापि स्वीकार नही है।राजनिति से हमारा कोई सम्बन्ध नही, लेकिन यदि हम आपको सतर्क ना करें तो गाय नही बचेगी।और अगर गाय न बची तो ये संसार भी नही बचेगा।

गौमतदाता सभा के पश्चात श्री जय अग्रवाल जी ने सपरिवार अपने आवास पर शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का पूजन कर शंकराचार्य जी महाराज की आरती उतारी।

फारबिसगंज युवा मारवाड़ी मंच द्वारा आज से संचालित हो रहे रोटी बैंक का शंकराचार्य जी महाराज ने उद्घाटन किया।रोटी बैंक की गाड़ी रोज तीन घण्टे निर्धारित समय से हिंदुओं के घर के आमने गाड़ी खड़ी रोटी एकत्र करेगी।जिस रोटी को गौमाता को समर्पित किया जाएगा।इस अक्षयपुण्य कार्य मे हिंदुओ ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु सहमति व्यक्त किया।

मतदाता सभा मे प्रमुख रूप से सर्वश्री-अखिलेश ब्रम्ह्चारी, भावानंद ब्रम्ह्चारी, प्रधान पुरुषेश्वरानंद ब्रम्ह्चारी सहित हजारों की संख्या में गौभक्त व धर्मप्राण बिहारवासी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारीद्वय संजय पाण्डेय व शैलेन्द्र योगी ने दी है।

डीएम की अध्यक्षता में आई0जी0आर0एस0 की बैठक कलेक्टेड्ट सभागार में आयोजित की गई

शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, गलत स्पेशल क्लोज़ पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आईजीआरएस मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, तहसील दिवस संदर्भ सहित अन्य संदर्भों के सापेक्ष निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों/प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में डिफाल्टर श्रेणी व असंतुष्ट फीडबैक से सम्बन्धित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपेक्षित सुधार का निर्देश दिया। आईजीआरएस समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहां कि जिन विभागों में शत प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक है उन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसंवाद दिवस पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक कराए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही पूरे मनोयोग से कार्य करें, जिससे जनपद की रैंक अच्छी बनी रहे। यह भी कहे कि शिकायतों को अधिकारी कटेगरी वाईज कर सही ढंग व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान एक्सईएन विद्युत के 08 संदर्भ में सही आख्या रिपोर्ट न लगाने व असंतुष्ट फीडबैक 18 प्रकरण होने साथ ही बैठक में अनुपस्थित होने पर, कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस के साथ शासन को पत्र लिखने को संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। तहसीलदार भदोही के लंबित प्रकरण अधिक होने पर असंतुष्ट फीडबैक के 85 प्रकरण होने पर तहसीलदार भदोही का वेतन रोकने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया, साथ ही स्वस्थ विभाग की सबसे ज्यादा सी श्रेणी के 11 प्रकरण लंबित होने पर व सही रिपोर्टिंग न करने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रमुख सचिव को पत्र लिखने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया।

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश शिकायतों का, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर शिकायतकर्ता को वार्ता कर संतुष्ट करने के उपरान्त ही आख्या अपलोड की जाए। केवल वे ही शिकायत स्पेशल क्लोज़ की जाए, जो पोर्टल पर उपलब्ध स्पेशल क्लोज़ की श्रेणी में आती हो। गलत फ्लैग लगाकर स्पेशल क्लोज़ करने पर कार्यवाही की जाएगी। प्रायः यह देखा जा रहा है कि जनपद स्तर से एक ही शिकायत को कई बार फीड किया जा रहा है एवं एक ही मोबाईल नंबर से अलग अलग शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। विश्लेषण में यह भी पाया गया है की मोबाईल नंबर शिकायतकर्ता का न होकर किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति का है। जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत है उसी से जांच कदापि न कराई जाए। यह भी समीक्षा कर लें की उनके यहाँ किस क्षेत्र या किस विभाग शिकायत श्रेणी मे सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं और उसका निराकरण कराएं। उदहारणर्थ कतिपय जनपदों में प्रमाणपत्र बनाने के संबंध में अधिक शिकायत दर्ज हो रही हैं।

पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद स्तर से निस्तारण की गुणवत्ता का क्रॉस वेरीफिकेशन करने के उपरान्त ही आख्या अपलोड या स्पेशल क्लोज की कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निरस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी फरियादियों/शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के प्रति बेहद गम्भीर है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करके रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के डिफाल्टर होने व निस्तारित शिकायतों की खराब गुणवत्ता पाये जाने पर कुछ विभागीय अधिकारियों को इसमें सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दिया, कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये कि निस्तारण की गुणवत्ता खराब होने के कारण उच्च स्तर से शिकायतें पुनः वापस आ जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष भी अवश्य सुना जाए और सदंर्भो के निस्तारण के परिणाम से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। क्योंकि शिकायतकर्ता की संतृष्टि ही संदर्भो का निस्तारण का मूल लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस का पैरामीटर बदल गया है असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों को सही ढंग से निस्तारण कराए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, डीडीओ ज्ञानप्रकाश, डीसी मनरेगा राजाराम, जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा, समस्त उप जिलाधिकारी, ईडीएम आशुतोष श्रीवास्तव एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रीमद्भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है-पं विष्णूकान्त शास्त्री महाराज

भदोही। औराई विकास खंड क्षेत्र के कैयरमऊ दीनानाथपुर गांव में धनेश मिश्रा के निज आवास पर चल रहे श्रीमद्भागवत कथा में कथा वाचक पं विष्णूकान्त शास्त्री जी महाराज ने कहा कि श्रीमद भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल्पवृक्ष के समान है। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है, वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्रीकृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। महाराज जी ने कहा कि भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है, जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है। साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती ।भगवान की कृपा से ही भक्त का कल्याण संभव है। पं विष्णूकान्त शास्त्री महाराज ने भक्ति और भक्त के बारे में विस्तार से बताया। महाराज ने कहा कि जीवन यापन करने में भक्ति तथा धन का संचय करना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भक्ति और मोक्ष की कल्पना करना ही बेकार है। पं विष्णूकान्त शास्त्री महाराज जी ने कहा कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करने पर ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान की कृपा केवल उन्ही पर होती है जो सच्चे मन से और निश्चल भाव से भक्ति करते है।

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों के मामलो को निस्तारण के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक

लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों के मामलो के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक कलेक्टेट्रट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सितम्बर 2025 तक जनपद के कुल 21 विभागों द्वारा 445 लम्बित याचिका है। जिनमें माह 2025 में 313 वादों में जबाब दाखिल किया गया है, 132 वाद अवशेष है कुल 01 अवमानना वाद है। उप जिलाधिकारी भदोही 86, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर 88, उप जिलाधिकारी औराई 68, अपर जिलाधिकारी वि0 रा0 11, अपर जिलाधिकारी न्यायिक 06, मुख्य विकास अधिकारी 22, मुख्य चिकित्साधिकारी 10, विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी 43, तहसीलदार भदोही 26, तहसीलदार ज्ञानपुर 23, तहसीलदार औराई 23, सहित अन्य विभागों की याचिकाएं लम्बित है।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी गलत रिपोर्ट न लगायी जाय। अधिकारियों द्वारा जो भी इन्स्ट्रक्शन दाखिल कराया जाय, उसकी एक फोटोकापी वाद लिपिक को भी अवश्य दे, जिससे वह अपडेट कर सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पुराने लम्बित वादों में स्पष्ट लिखा जाय कि वर्तमान अधिकारी जनपद में कब ज्वाईन किये है, जिससे न्यायाधीशों को वाद फाईल समझने में सुविधा जनक हो। सुनवाई तिथि के पहले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट की साइट पर जाकर देख लिया जाय कि कोई नई डाइरेक्शन तो नही दिया गया है। जिलाधिकारी ने लम्बित वादों के प्रकरण पर सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रभावी न्यायिक तरीको से वादों का निस्तारण कराने पर बल दे।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह द्वारा गैंगेस्टर के मामलों में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर बल दिया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को नवीनतम गैंग चार्ट के विभिन्न बिन्दुओं व आयामों से अवगत कराया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार चक सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व लम्बित वादों से सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सात सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

गोपीगंज। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष अमृत लाल अग्रहरि के नेतृत्व में सात सूत्रीय मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सम्बोधित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौपा गया। सौपे गये मांग पत्र के माध्यम से मांग किया कि सुदुर अंचलजो में आम जनमानस की समस्याओ को उठाते साथ ही शासन प्रशासन की भी आवाज बनते है लेकिन सरकार की नजर ग्रामीण अंचल के पत्रकारों पर नजर नही पड़ रही है। कठिन परिस्थितियो में भी ग्रामीण पत्रकारिता को लोकतंत्र की सशक्त धारा को बनाये रखने में अग्रणी भूमिका भी निभाते है लेकिन इन शासन की नजर नही पड़ रही है। मांग किया कि अन्य संगठनो की भांति दारूल सफा और ओसीआर में पत्रकार कार्यालय का गठन किया जाय।

ताकि दूर दराज से लखनऊ जाने वाले पत्रकार ठहर सके। मान्यता प्राप्त पत्रकारो की तरह ही ग्रामीण पत्रकारो को योजना का लाभ दिया जाय। पत्रकारो को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाय। साथ ही 60 वर्षीय पत्रकारो कों पेशन का लाभ दिया जाय। ग्रामीण पत्रकारो के विरूद्घ कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाय। प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकार को किसान बीमा योजना की तरह ही तत्काल पांच लाख की सहायता राशि परिजनो को दिया जाय। प्रदर्शन करने वालो में राकेश द्विवेदी, सुशील पाण्डेय, अमर बहादुर सिंह, अब्दुल कयूम, मुकेश दूबे, रामकुमार वर्मा, आशीष मोदनवाल, दिनेश यादव ददा, आजाद खां, जयप्रकाश जायसवाल, अब्दुल वाहिद, नेहाल , अशोक मौर्यआदि लोग मौजूद रहे।

पेशी पर आए बाल किशोर न्यायालय से फरार

भदोही। जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी आलमपुर नई बस्ती थाना व जनपद भदोही को बाल किशोर न्यायालय में लाया गया था। मुलजिम सुरक्षा ड्यूटी में लगे 1.30नि0 अवधनरायन सिंह पीएनओ-942190180 2.30नि0 विष्णुकांत मिश्रा पीएनओ- 972410236 को चकमा देकर फरार हो गया। मुलजिम सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरते जाने पर उपरोक्त दोनों उपनिरीक्षकों को निलंबित करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आज से करीब 10 दिन पहले फरार अभियुक्त द्वारा पूर्व से जेल में निरूद्ध नियाज निवासी आलमपुर थाना व जनपद भदोही से 3, 00, 000/- की लालच देकर अपने आप को भगाने का तरकीब बनाया था। नियाज के पुत्र अली को अपने पेशी पर मोटरसाइकिल के साथ बुलाया था। आज 16.09.2025 को समय लगभग दोपहर 12:30 बजें बनाए गए साजिश के तहत अली पुत्र नियाज निवासी आलमपुर थाना व जनपद भदोही द्वारा मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था।

हलवाई ने एचडीएफसी बैंक से किया 5 करोड़ का फ्रॉड

500 रुपए में खुलवाया खाता फिर कर दिया बड़ा घोटाला

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के हाथरस जिले में एक हलवाई की दुकान चलाने वाले ने 5 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। हलवाई ने 500 रुपए में एचडीएफसी बैंक में खाता खोल कर बैंक के साथ धोखाधड़ी का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले युवक ने अपने सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में परिवर्तित कराया। फिर 5 करोड़ से अधिक का फ्रॉड कर दिया। वहीं जब पुलिस और एसओजी टीम को इसकी जानकारी हुई तो बैंक के साथ 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में आकाश नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आपको बता दें कि कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र स्थित मोहल्ला विष्णुपुरी निवासी आकाश पुत्र मां चामुंडा देवी नाम से एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है। आकाश ने एचडीएफसी बैंक में महज 500 रुपए से खाता खुलवाया। फिर उसी खाते को करंट खाते में तब्दील करा दिया। फिर बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का खेल शुरू कर दिया। आरोपी ने कई बार बैंक से ओवर ड्राफ्ट कर 5 करोड़ से अधिक की धनराशि निकाल ली। बैंक से ओवर ड्राफ्ट रुपया ले कर 3.5 करोड़ रुपये लगाये ग्रो से शेयर मार्केट में लगा दिए। यह पूरा मामला हाथरस कोतवाली सदर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक से जुड़ा हुआ है।

वहीं पुलिस अधीक्षक चिरंचीव नाथ सिन्हा ने मामले का खुलास करते हुए बताया कि जब बैंक से 5 करोड़ के फ्रॉड की जानकारी हुई तो इस मामले में एसओजी टीम गठित कर जांच कराई गई तो बड़ा ही चौंकने वाला मामला सामने निकल कर आया। जांच के दौरान नए तरीके से बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में एचडीएफसी के क्लस्टर हैड ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया है। जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके कब्जे से 6 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।

भाजपा की पूर्व विधायक के बेटे की दबंगई वायरल!

अजय राय बोले- सत्ता के गुंडे कर रहे अत्याचार, अब जनता देगी जवाब!

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व विधायक के पुत्र पर दबंगई का आरोप लगाया है। राय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा 'वाराणसी की पवित्र धरती पर बीजेपी की पूर्व विधायिका सुनीता सिंह के बेटे की दबंगई। परिवार का गेट बंद कर जबरन बाउंड्री पर कब्जा। क्या यही है भाजपा का 'सुशासन'। जहां सत्ता संरक्षित गुंडे खुलेआम अत्याचार करें और पीड़ित दर-दर भटकें। जनता सब देख रही है, अब अन्याय करने वालों को जवाब देना होगा।'

दरअसल वाराणसी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा इलाके का बताया जा रहा है। डीसीपी काशी ने इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखकर बताया ' प्रकरण भूमि व रास्ते संबंधित विवाद का है, शांति व्यवस्था हेतु दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है तथा निस्तारण हेतु समक्ष न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मुस्कान से दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी

जेल में बदल रही साहिल की सोच; मैनेजर की नौकरी करने वाला बना किसान, रोज कमा रहा 40 रुपए

लखनऊ **(एजेंसी)**। एक समय मैनेजर की नौकरी करने वाला साहिल, जो सौरभ हत्याकांड के चलते जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, अब एक नई राह पर है। नीले ड्रम में पति की लाश छिपाने वाले इस चर्चित मामले में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मुख्य आरोपी थे। दोनों फिलहाल मेरठ जेल में सजा काट रहे हैं।

जेल में बिताए जा रहे समय ने साहिल की जिंदगी की दिशा बदल दी है। उसने नशे की लत छोड़ दी है और अब वह खेतों में काम कर रहा है। जेल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, साहिल नियमित रूप से जेल परिसर में खेती करता है और उसे प्रतिदिन 40 रुपये मेहनताना दिया जाता है। महीने भर में उसे छुट्टियों को छोड़कर लगभग 900 से 1000 रुपये तक मिलते हैं।

जेल अधीक्षक ने बताया कि साहिल अब फसल, बीज और मौसम की जानकारी रखने लगा है। सिंचाई से लेकर जुताई तक वह हर काम में खुद शामिल होता है। मिट्टी से जुड़कर वह अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। साहिल ने जेल में बातचीत के दौरान कहा, 'मुस्कान से दोस्ती करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी के कारण मैं अपराध के रास्ते पर चला गया। अब मैं खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ।' जहाँ साहिल के परिवार के सदस्य, जैसे उसकी नानी और भाई, उससे मिलने जेल आते हैं, वहीं मुस्कान के परिवार से कोई भी अब तक उससे मिलने नहीं आया है।

हमारा सीएम कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो, नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्यमंत्री बनाने के लगे नारे

बोले- 2028 में बनेगी कांग्रेस सरकार

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और तब विधायक बिकने की कोई संभावना नहीं रहेगी।

अनूपपुर दौरे के दौरान आयोजित एक जनसभा में कार्यकर्ताओं ने उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते हुए नारे लगाए 'हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो।' इस पर सिंघार ने कहा कि 'मैंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। जब तक जीवन है, मैं जनसेवा करता रहूंगा। पार्टी जो तय करेगी, वही मान्य होगा। 2028 अभी दूर है।

सिंघार ने इस दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'आयोग का कमिश्नर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। राहुल गांधी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो जवाब मिला कि महिलाएं थीं, इसलिए फुटेज नहीं दी जा सकती। मतदान के अंतिम घंटे में अचानक 2-5 प्रतिशत वोट कैसे बढ़ जाते हैं? इसका मतलब है कि 200-300 अतिरिक्त लोग बूथ पर पहुंचे, जो शक पैदा करता है। चुनाव आयोग का भाजपा की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है।' नेता प्रतिपक्ष ने खाद की किल्लत का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है, लेकिन हकीकत में किसान पूरे प्रदेश में खाद की कमी से परेशान हैं।

सिंघार के इन बयानों से एमपी की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सीएम पद की मांग और भाजपा नेताओं के संपर्क में होने के दावे ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है।

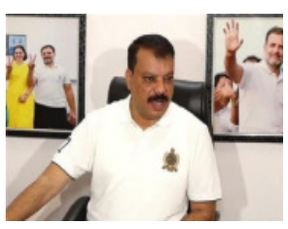

शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ भाजपा बोली- कांग्रेस बराबर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ़ की है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर धर्म कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। अफरीदी ने भारत-पाकिस्तान मैच पर एक पैनल चर्चा के दौरान पाकिस्तान के समा टीवी से बातचीत में कहा कि यह सरकार (भारत में) सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा धर्म और मुस्लिम-हिंदू कार्ड खेलती है। यह बहुत ही घटिया मानसिकता है। राहुल गांधी की सोच बहुत सकारात्मक है। वह बातचीत में विश्वास रखते हैं। क्या एक इज़राइल काफ़ी नहीं है कि आप दूसरा इज़राइल बनने की कोशिश कर रहे हैं?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अफरीदी की टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक सहयोगी मिल जाता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हाफिज सईद के बाद, अब शाहिद अफरीदी (आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी) राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं... कोई आश्चर्य नहीं! भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक सहयोगी मिल जाता है। सोरोस से लेकर शाहिद तक... कांग्रेस = इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस-पाकिस्तान का याराना बहुत पुराना है और यह सबसे पुरानी पार्टी अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर 26/11 के मुंबई हमलों, पुलवामा और पहलगाम पर क्लीन चिट तक हमेशा पाकिस्तान की ही बात दोहराती है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत के दुश्मन राहुल गांधी की जय-जयकार कर रहे हैं और भारतीयों को उनकी वफ़ादारी का अंदाज़ा है।

मालवीय नें पर लिखा कि कट्टर हिंदू-द्वेषी शाहिद अफरीदी, जो भारत के खिलाफ़ ज़हर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की तारीफ़ करने लगे हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल पाकिस्तान के साथ 'बातचीत' चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति की तुलना गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई से करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं। ऐसा क्यों है कि हर भारत-द्वेषी राहुल गांधी में एक दोस्त ढूंढ लेता है? जब भारत के दुश्मन आपकी जय-जयकार करने लगते हैं, तो भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी वफ़ादारी किसकी है।

रविवार को दुबई में एशिया कप के ग्रुप चरण के मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। इस मैच की भारतीयों ने कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर सवाल उठाए। यह मैच ऐसे समय में खेला जा रहा है जब महज चार महीने पहले ही जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, की हत्या कर दी थी। विपक्षी दलों ने भी बीसीसीआई को मैच आयोजित करने की अनुमति देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की है।

2000 ट्रैक्टरों के साथ उज्जैन में किसानों का महाआंदोलन, भाजपा नेता ने भी दिया समर्थन, सिंहस्थ में स्थाई सिटी का विरोध

उज्जैन **(एजेंसी)**। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी सिटी बसाने के लिए की जा रही लैंड पुलिंग योजना के विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। अब तक 2000 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 5000 से अधिक किसान शहर में पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि आंदोलन में 10 हजार किसान शामिल होंगे। किसान जहां लैंड पुलिंग योजना का विरोध कर रहे हैं, वहीं उन्होंने सरकार के सामने 15 सूत्रीय मांगें भी रखी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर इन मांगों को अनसुना किया गया, तो वे गांवों से दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे।

आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में किसानों का जमावड़ा जारी है। इसमें सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़े 17 गांवों के साथ आसपास के अन्य इलाकों के किसान भी शामिल हैं। आंदोलन का आह्वान भारतीय किसान संघ, जिला उज्जैन मालवा प्रांत ने किया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन भी किसानों के बीच पहुंचे और आंदोलन का समर्थन जताया, हालांकि कुछ देर बाद वे लौट गए। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में गलती कर रही है। सिंहस्थ हजारों सालों से होता आ रहा है, तब न केंद्र सरकार थी और न ही राज्य सरकार। यहां स्थायी संरचनाओं की जगह अस्थायी सुविधाएं बनाई जानी चाहिए।

टीटीवी दिनाकरण ने पलानीस्वामी पर साधा निशाना गठबंधन की किसी भी संभावना को किया खारिज

चेन्नई **(एजेंसी)**। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि 2026 के चुनावों के बाद, पलानीस्वामी बीच सड़क पर खड़े रह जाएँगे। तंजावुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, दिनाकरन ने कहा, 'एडप्पादी दावा करते हैं कि उन्होंने कृतज्ञता दिखाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह 'शैतान द्वारा शास्त्र पढ़ने' से कम नहीं है। पलानीस्वामी को भाजपा ने नहीं, बल्कि उन 122 विधायकों ने बचाया था जो संकट के दौरान कूवथुर में ठहरे हुए थे।'

दिनाकरन ने कहा कि पलानीस्वामी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया, कि वह झूठ का पुलिंदा हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 2026 के चुनावों में तमिलनाडु की जनता पलानीस्वामी को पूरी तरह से नकार देगी। पार्टी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, 'एएमएमके के एडप्पादी के साथ गठबंधन करने की कोई संभावना नहीं है।' उनके अनुसार, पलानीस्वामी ने 'दो पत्ती' चुनाव चिन्ह और धनबल का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उनका वोट शेयर 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा।

दिनाकरन ने कहा कि एडप्पादी को कृतज्ञता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है–यह शैतान द्वारा शास्त्रों का जाप करने जैसा है। वह कोई डॉन नहीं हैं। हर समस्या के लिए पलानीस्वामी स्वयं ज़िम्मेदार हैं। वह हथेली पर रखे आंवले की तरह हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख नैनार नागेंद्रन की भी आलोचना करते हुए कहा, 'नागेंद्रन अपने बयान बदलते रहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करूँगा, और न ही मैंने नागेंद्रन से ऐसा कभी कहा।'

इससे पहले 7 सितंबर को, भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने कहा था कि एएमएमके के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) छोड़ने के लिए वह ज़िम्मेदार नहीं हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह टीटीवी दिनाकरन को पकड़ने के लिए तैयार हैं।

सुप्रसिद्ध कुबेश्वर धाम में लगे बैनरों से हलचल! गैर हिंदुओ का प्रवेश मना!

कथावाचक मोहित बोले- गाय खाने वाले विधर्मियों का यहां क्या काम?

सीहोर **(एजेंसी)**। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम मार्ग पर जगह-जगह एक बैनर चर्चाओं का केन्द्र बन गया है। दरअसल बैनर पर कुबेश्वर धाम प्रांगण में गैर हिंदुओ का आना सख्त मना लिखा है जो चर्चाओं का विषय बन गया है। बैनर में निवेदक कर्ता के तौर पर सकल हिन्दू समाज, विश्व हिंदू परिषद ओर बजरंग दल लिखा गया है। वहीं जब कुबेश्वर धाम मार्ग पर दुकानदारों ओर भक्तों से इस बैनर के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो किसी ने भी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया लेकिन दबी जुबान से गैर हिंदुओं के मंदिर पर एंट्री से वो खुश दिखे।

वहीं कथावाचक पंडित मोहित पाठक से साफ कहा है कि धाम पर भक्तों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन कुछ विधर्मी लोग महिला भक्तों से छेड़छाड़ करते है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते है। ये बैनर ऐसे ही विधर्मी प्रवृत्ति के लोगो के लिए एक चेतावनी है।पाठक ने कहा कि गाय खाने वाले आदमी को हमारे किसी भी मंदिर या धाम में आने की आवश्यकता नही है ।यहां पर तिलकधारी ही आएंगे कोई गाय को खाने वाला नहीं आएगा। गाय खाने वाले लोगों को ऐसे स्थानों पर घुसने ही नहीं देना चाहिए। पाठक ने कहा कि हमारे मंदिर को कोई भी मुल्ला और टोपीवाला नहीं चाहिए ये हिंदुओ के स्थल हैं और यहां हिंदू ही आने चाहिए।

तेजस्वी यादव पर दर्ज हुई प्राथमिकी 'माई बहन योजना' के नाम पर ठगी का आरोप

पटना **(एजेंसी)**। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सहित चार नेताओं पर ठगी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस प्राथमिकी में गुड़िया देवी ने तेजस्वी यादव के साथ राजद के सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और राजद नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कुर अहमद उस्मानी को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि राजद प्रायोजित माई बहन योजना का फॉर्म भरवाते हुए उससे 200 रुपये लिए गए।

गुड़िया ने अपने आरोप में लिखा है कि इस योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह लाभ देने की बात कही गई है और इसके एवज में उससे फॉर्म की कीमत 200 रुपए लेने के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल की भी जानकारी ली गयी। गौरतलब है कि राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार आने भाषणों में कहते आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के किए 'माई बहन योजना' के तहत उन्हें 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। उन्होंने अपने भाषणों में कहीं नही कहा है कि इसके लिए चुनाव से पहले फॉर्म भरना होगा और 200 रुपए की फीस देनी होगी। इसी संदर्भ में गुड़िया देवी ने अपनी प्राथमिकी में दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना के थानाध्यक्ष को लिखा है कि उन्होंने जब 200 रूपये के फॉर्म और 2500 रूपये खाते में आने की बात अपने पति मिथिलेश भगत को बताई तो उन्होंने इस ठगी को उजागर किया।

तेजस्वी और विपक्ष के चार नेताओं के ऊपर दर्ज प्राथमिकी को उसी दिन बिहार सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश कुमार पर दर्ज प्राथमिकी के साथ जोड़ा जा रहा है। जीवेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक युट्यूबर को गाली देने के साथ पिटाई की और कपड़े फाड़ दिए।

बौखला उठा पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर नेशनल टीवी पर सूर्यकुमार को दी गाली

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच के बाद खड़ा हुआ विवाद और गहरा गया है। एक टीवी शो के दौरान पाकिस्ता ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को झटका देते हुए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से साफ इनकार कर दिया है।

दरअसल, 14 सितंबर को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। टॉस के वक्त और मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने दूरी बनाए रखी थी। पीसीबी ने इस मामले में आईसीसी से शिकायत करते हुए कहा था कि इसके लिए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट जिम्मेदार हैं और उन्हें हटाया जाए। हालांकि, जांच के बाद आईसीसी ने यह शिकायत खारिज कर दी और पीसीबी की मांग को ठुकरा दिया।

इस विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि 'मैं हैरान हूं और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। यह देखकर बहुत दुख हुआ। हैंडशेक न करने पर कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में इसे भुला देना ही बेहतर है। घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रिकेट का असली मतलब यही है कि मैच के बाद हाथ मिलाएं और गरिमा बनाए रखें।' वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक न करने की सलाह दी थी। गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा था कि न तो हाथ मिलाएं और न ही किसी विवाद में पड़ें।

भारतीय टेनिस की मदद के लिए सिर्फ पद पर काबिज होना ही एकमात्र रास्ता नहीं है : सानिया

दुबई **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अनुसार देश के प्रत्येक खेल महासंघ की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में चार महिलाओं का होना अनिवार्य है लेकिन दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा का मानना है कि युवा प्रतिभाओं को तराशने में उनकी भूमिका अखिल भारतीय टेनिस संघ में एक पद से कहीं अधिक है। खेलों में भारतीय महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक रहीं सानिया ने अपने दुबई स्थित आवास से पीटीआई से कई मुद्दों पर बात की जिनमें टेनिस में वेतन समानता से लेकर स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारत की डेविस कप जीत शामिल रहीं जबकि उन्होंने 16 साल की माया राजेश्वरन रेवती की विशेष प्रतिभा पर भी बात की है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह निकट भविष्य में खेल प्रशासन में दिखाई दे सकती हैं तो सानिया ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मदद करने के लिए उस शक्तिशाली पद पर होना ही एकमात्र तरीका है। ईमानदारी से कहूं तो मेरा यही जवाब है। अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं कर पाऊंगी, तो क्या मैं उस पद पर रहकर और योगदान दे पाऊंगी तो मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। लेकिन क्या मैं इसका लक्ष्य बना रही हूं तो मेरा जवाब है, नहीं। क्योंकि यह मेरा लक्ष्य नहीं है।'

सानिया के लिए भारतीय टेनिस की अगली पीढ़ी के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए कोई पद पर बैठना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, "मेरा लक्ष्य युवा पीढ़ी के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों और विशेषकर युवा लड़कियों की मदद करना है क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा आदर्श नहीं हैं जिनसे वे प्रेरणा ले सकें।' सानिया ने कहा, 'मैं अपने अनुभव साझा करना चाहती हूं। और अगर मुझे इसके लिए किसी तंत्र में शामिल होने का मौका मिलता है और इससे मुझे सिर्फ फोन पर बात करने या कोर्ट पर उनकी मदद करने या किसी भी तरह की अन्य चीज से ज्यादा मौके मिलते है तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।' उन्होंने कहा, 'लेकिन मेरा फोकस इस पर नहीं है। यह मेरा लक्ष्य नहीं है।'

सानिया के बाद भारत में महिला टेनिस में कौन उभरती हुई प्रतिभा है, यह पूछने पर उन्होंने माया राजेश्वरन रेवती का नाम लिया । माया स्पेन में राफेल नडाल अकादमी में ट्रेनिंग लेती हैं। सानिया ने कहा, 'माया में काफी प्रतिभा है। मेरे बाद कौन आएगा, यह ऐसा सवाल है जिससे हम शायद पिछले 25 साल से जूझ रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'तो एक 15-16 साल की युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ते हुए देखना और अपने आयु वर्ग के ऊपर वर्गों में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हुए देखना अच्छा लगता है।'

एकल में पूर्व 27वें नंबर की खिलाड़ी सानिया ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ डेविस कप मुकाबला जीतने के लिए भारतीय पुरुष टीम की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'डेविस कप टीम तारीफ की हकदार है जिसने यूरोप में शायद 31 या 32 साल बाद स्विट्जरलैंड को हराकर एक यूरोपीय टीम के खिलाफ पहली बार जीत हासिल की है। सुमित नागल ने अच्छा नेतृत्व किया और पिछले डेढ़ साल में एक तरह से शानदार वापसी की है।'

नागल के बारे में बात करते हुए सानिया ने कहा कि भारत का शीर्ष एकल खिलाड़ी अभी 28 साल का है। उन्होंने कहा, 'लेकिन यह खिलाड़ी अब उतना युवा नहीं है। ये खिलाड़ी 28, 29, 30 साल के हैं। और टेनिस के लिहाज से ये इतने युवा नहीं हैं। यही सच है। लेकिन सुमित ने पिछले कुछ सालों से अकेले ही अविश्वसनीय काम किया है और डेविस कप में भी जीत हासिल की है।'

पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, एशिया कप का बॉयकॉट नहीं करेगा, यूएई में ही रहेगी टीम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर एशिया कप 2025 का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी। जिसके बाद आईसीसी ने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया। जिसके बाद पीसीबी की हेकड़ी निकल गई है। कहा जा रहा है कि, पाकिस्तान अब कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तानी टीम यूएई में ही रहेगी और एशिया कप के अन्य मुकाबले भी खेलेगी।

ईएसपीएन क्रिकन्फो की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान मेजबान यूएई से भिड़ेगा। ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करचुका है ऐसे में बुधवार का मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान या यूएई में ये जो भी ये मैच जीतेगा, सुपर-4 के लिए उसका दावा मजबूत हो जाएगा।

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की शिकायत की थी। बोर्ड ने उन्हें एशिया कप से तत्काल हटाने की मांग की थी। पीसीबी अधिकारियों ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा। आईसीसी ने मंगलवार को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी।

पूरे मामले में शुरुआत 14सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच से हुई। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। एकतरफ मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ भी गए, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो गया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के कप्तान आगा ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन का बहिष्कार किया।

हाथ ना मिलाने की घटना के बीच पोंटिंग विवादों में पूर्व क्रिकेटर को आगे आकर बतानी पड़ी सच्चाई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने रविवार को एशिया कप के ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया द्वारा हाथ मिलाने की अनदेखी पर टिप्पणी करने के झूठे आरोप के बाद एक बयान जारी किया है और खुद आगे आकर इस सारे घटनाक्रम पर सच्चाई बतानी पड़ी। भारत द्वारा पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत हासिल करने के बाद खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक बयान फैलने लगा जिसमें कहा गया कि पोंटिंग ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर न निकलने पर भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार की आलोचना की थी।

एक्स यूजर्स ने स्काई स्पोर्ट्स पर पोंटिंग की यह टिप्पणी गलत तरीके से पेश की कि, 'यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा और भारत बड़ा लूजर है जिस तरह से पाकिस्तानी टीम अंत में हाथ मिलाना चाहती थी, उसने उन्हें सज्जनों के खेल का चैंपियन बना दिया है जबकि भारत हमेशा हारता रहा है।' सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत गुस्सा दिखाया और पोंटिंग की भारतीय टीम पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की।

पोंटिंग ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा, 'सोशल मीडिया पर मेरे नाम से कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं। कृपया जान लें कि मैंने स्पष्ट रूप से वे बयान नहीं दिए हैं और वास्तव में मैंने एशिया कप के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।'

अमेरिकी टैरिफ ने तोड़ी कालीन उद्योग की कमर, 2, 500 करोड़ के ऑर्डर अटके

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्क ने उत्तर प्रदेश के भदोही-मिर्जापुर के कालीन उद्योग की कमर तोड़ दी है। 'कालीन बेल्ट' कहलाने वाले भदोही-मिर्जापुर में कई कारखानों पर ताले लटक गए हैं और कुछ में नाम मात्र का काम चल रहा है।

भदोही के हाथ से बुने कालीन की अमेरिकी बाजार में जबरदस्त मांग थी और सैकड़ों कारोबारी सिर्फ वहीं से मिले ऑर्डरों पर फल-फूल रहे थे लेकिन 'ट्रंप टैरिफ' ने तस्वीर बदल दी। करीब 2, 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर अटक गए हैं और कारखाना मालिक मजदूरों की छंटनी करने को मजबूर हो गए हैं। नतीजतन, कालीन धंधे से जुड़े लगभग 7 लाख परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट मंडरा रहा है।

भारत हर साल करीब ?17, 000 करोड़ के हाथ से बुने कालीन अमेरिका और दूसरे देशों को निर्यात करता है। इनमें से ?10, 500 करोड़ का माल सिर्फ भदोही-मिर्जापुर से जाता है। सबसे अहम बात यह है कि यहां से तैयार होने वाले कालीनों का करीब 60इ यानी ?6, 000 से ?6, 500 करोड़ का निर्यात अकेले अमेरिकी बाजार में होता है।

भदोही-मिर्जापुर के पर्शियन स्टाइल वाले हैंड-टफ्टेड और हैंड-नॉटेड कालीन बेहद कीमती होते हैं लेकिन भारत में इनकी खपत न के बराबर है–सिर्फ 2इ कालीन ही घरेलू बाजार में बिकते हैं। कालीन कारोबारी इश्तियाक बताते हैं कि देश के होटल, मॉल और थिएटर में ज्यादातर मशीन से बने कालीन ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए भदोही के कारोबारी अमेरिकी डिमांड के हिसाब से ही माल तैयार करते हैं। अब नए बाजार ढूंढना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि उसमें वक्त भी लगेगा।

हाथ से बुने कालीनों की डिमांड साल में सिर्फ तीन महीने अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। इसके लिए मई-जून से ही उत्पादन शुरू हो जाता है लेकिन इस बार अप्रैल से ही अनिश्चितता बनी रही और जो ऑर्डर मिले भी, वे या तो कैंसिल हो रहे हैं या घाटे में पूरा करने की नौबत आ गई है।

जीएसटी छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें खुदरा विक्रेताः वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक पत्र में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी में कमी को जीएसटी छूट के रूप में दर्शाना चाहिए और उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

डीपीआईआईटी ने कहा, "अपने नेटवर्क के माध्यम से वे 'जीएसटी के कारण छूट' को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। उदाहरण के लिए - अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पोस्टर/फ्लायर्स और विज्ञापन (प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन) के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए।" विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री के आंकड़ों पर नजर रखी जाए और विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दी जाए।

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक, लगभग 400 उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। 22 सितंबर से, जीएसटी स्लैब संरचना बदल जाएगी। आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर पांच प्रतिशत और बाकी सभी उत्पादों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। 12 और 28 प्रतिशत की मौजूदा स्लैब को हटा दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे में ज़्यादातर रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें और किराना सामान पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे, जबकि ब्रेड, दूध और पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा।

वेदांता का कारोबार विभाजन चालू वित्त वर्ष में ही पूरा होने की संभावना-सीईओ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वेदांता रिसोर्सेज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) देशनी नायडू ने मंगलवार को कहा कि भारतीय शाखा वेदांता लिमिटेड का कारोबार विभाजन इस वित्त वर्ष में ही पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान कंपनी के पुनर्गठन पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) वेदांता लिमिटेड के प्रस्तावित कारोबार विभाजन पर बुधवार को सुनवाई करने वाला है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी के प्रमुख व्यवसायिक विभागों को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया जाएगा।

नायडू ने कहा, "मैं बेहद आशावादी हूं। फिलहाल मेरा काम संगठन का इस तरह पुनर्गठन करना है जैसे हम पहले ही अलग-अलग कारोबार पर आधारित कंपनी बन चुके हों।" उन्होंने कहा, "इस बारे में बुधवार को सुनवाई होने वाली है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह सुनवाई एनसीएलटी की मंजूरी प्रक्रिया की ही दिशा में बढ़ा कदम होगी।" वेदांता रिसोर्सेज की सीईओ ने कहा कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) से संबंधित मामला पहले ही सुलझ चुका है। एनसीएलएटी ने टीएसपीएल के कारोबार को मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड से अलग करने को मंजूरी दे दी है। यह आदेश चीन की सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प के साथ हुए समझौते के बाद आया। सेप्को टीएसपीएल की एक प्रमुख लेनदार थी और 1, 251 करोड़ रुपए के बकाया का हवाला देकर उसने कारोबार विभाजन का विरोध किया था।

उन्होंने एक सवाल पर कहा, "बाजार नियामक सेबी को मौजूदा कारोबार विभाजन योजना पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्होंने बेस मेटल यूनिट के विभाजन को लेकर और जानकारी मांगी है जिसे अब 'वन प्लस फोर विभाजन' के तहत नहीं किया जा रहा है।" इस कारोबार विभाजन की मंजूरी के बाद वेदांता के विभिन्न व्यावसायिक विभाग अलग-अलग इकाइयों के रूप में काम करेंगे। पुरानी योजना के तहत कारोबार विभाजन के बाद छह स्वतंत्र कंपनियां बनने वाली थीं लेकिन बाद में इस योजना को संशोधित कर चार स्वतंत्र कंपनियां बनाने का फैसला किया गया। कंपनी ने अपनी बेस मेटल यूनिट को मूल कंपनी में ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।

सोने की दौड़ में शेयर बाजार पीछे निवेशकों की बढ़ी गोल्ड में दिलचस्पी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पिछले एक साल में सोने ने 50.1इ का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि शेयर बाजार (बीएसई सेंसेक्स) इसी अवधि में 1.2इ गिर गया। सिर्फ हाल का ही नहीं, बल्कि पिछले 3, 5, 10 और 20 सालों में भी सोने का प्रदर्शन घरेलू शेयर बाजार से बेहतर रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने की तेजी की बड़ी वजह वैश्विक सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी और महंगाई से बचाव की मांग है। अभी भी करीब 25इ सोना सेंट्रल बैंक ही खरीद रहे हैं। वे इसे अमेरिकी ट्रेजरी के विकल्प और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता से बचाव के लिए डाइवर्सिफिकेशन टूल मान रहे हैं।

इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और डॉलर की कमजोरी ने भी सोने को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि हाल की तेज रैली के बाद आगे सोने में बढ़त सीमित हो सकती है। निवेश पोर्टफोलियो में 10-15इ सोने को रखना सही माना जा रहा है लेकिन पिछले साल जैसे ऊंचे रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

एडलवाइस म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के मुताबिक, सोना बनाम सेंसेक्स रेशियो इस समय 0.76 है, जबकि इसका लंबी अवधि का औसत 0.96 रहा है। इसका मतलब है कि इक्विटी में निवेश अब ज्यादा आकर्षक हो सकता है।

इतिहास भी यही बताता है–जब यह रेशियो 0.8 से नीचे गया है, तो अगले तीन सालों में सेंसेक्स ने औसतन 25.12इ रिटर्न दिया है, जबकि सोने ने सिर्फ 7.21इ यानी लंबे समय में इक्विटी बेहतर साबित हो सकता है, जबकि सोना महंगाई से बचाव के लिए जरूरी है।

60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने दर्ज कराए बयान, दोनों की बढ़ी मुसीबत!

ब्रिटेन में जन्मे व्यवसायी राज कुंद्रा भारत में रियल एस्टेट और खेल से लेकर ऑनलाइन व्यवसायों तक कई उपक्रमों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शादी की है। काफी समय से ये जोड़ी विवादों में बनीं हुई है। कभी किसी फ्रॉड केस में तो कभी अश्लीस फिल्में बनाने के अरोप में लाफी समय से कुंद्रा परिवारा और जांच एजेंसियों की तकरार जारी है। ताजा मामला 60 करोड़ रूपये से जुड़ा है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा का सोमवार को बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू के कर्मियों ने मामले के संबंध में कुंद्रा (50) से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। मीडिया की नजरों से बचने के लिए उनका बयान एक अज्ञात स्थान पर दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया, "हमने आज (सोमवार) कुंद्रा का बयान दर्ज किया और संभवतः अगले सप्ताह उन्हें फिर से तलब किया जाएगा क्योंकि अगले दौर की पूछताछ से पहले कई और गवाहों की जांच की जरुरत है।"

उन्होंने कहा कि सह-आरोपी शेट्टी को कोई समन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ईओडब्ल्यू अभी भी साक्ष्य एकत्र कर रही है। ईओडब्ल्यू अभिनेत्री और उनके व्यवसायी पति के खिलाफ मुंबई में दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। यह मामला एक प्रसिद्ध दंपति और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया, जिन पर एक व्यवसायी को उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित रूप से 60.4 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।

व्यवसायी दीपक कोठारी (60) ने यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो 'लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज' नामक एक 'गैर-बैंकिंग' वित्तीय कंपनी में निदेशक हैं। इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। एलओसी एक नोटिस होता है जिसका इस्तेमाल अधिकारी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने या उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए करते हैं। यह आव्रजन और सीमा अधिकारियों को उस व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए सचेत करता है।

एमी में मंगेतर बेनी ब्लैंको के साथ सेलेना गोमेज़का दिखा रोमांटिक अंदाज़, शादी से पहले प्यार का इज़हार!

सेलेना गोमेज़ ने 77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में अपने मंगेतर बेनी ब्लैंको के साथ एक आकर्षक लाल लुई वुइटन गाउन पहनकर शानदार एंट्री की। हाल ही में सगाई करने वाली इस गायिका और अभिनेत्री ने लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में रेड कार्पेट पर हाथों में हाथ डाले वॉक किया, जहाँ उन्हें उनकी हिट सीरीज़ 'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' के लिए नामांकित किया गया था। इस जोड़े की उपस्थिति रात के सबसे यादगार पलों में से एक थी। इस महीने के अंत में होने वाली अपनी शादी से पहले, गोमेज़ ने ब्लैंको के गाल पर किस दिया, जिससे प्रशंसकों और फोटोग्राफरों ने उनकी खूब सराहना की।

सेलेना गोमेज़ और उनके मंगेतर बेनी ब्लैंको भी एमी अवार्ड्स 2025 में बेहद खूबसूरत नज़र आए। पॉप स्टार जहाँ लाल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, वहीं बेनी ने पूरी तरह से काले रंग का आउटफिट चुना। लेकिन रेड कार्पेट पर दोनों ने अपने रोमांस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया! बेनी ने अपनी पार्टनर को किस किया और सेलेना शरमा गईं! रेड कार्पेट पर बेनी द्वारा सेलेना को किस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें बेनी उन्हें किस करते हुए पॉप स्टार को शरमाते हुए दिखाया गया है।

बता दें कि सेलेना और बेनी जल्द ही शादी करने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, पॉप स्टार ने बताया कि अगर उनका पार्टनर उनसे पाँच साल पहले मिलता, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। उन्होंने एल्योर को बताया 'वह कहते, 'हे भगवान, हमने इतना समय क्यों बर्बाद किया?' और मैं हमेशा कहती, 'तुम्हें तब मैं पसंद नहीं आती।' मैं उनके दिल, उनकी दयालुता, उनकी अजीबोगरीब आदतों की कद्र करती हूँ... वह मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़मीनी लोगों में से एक हैं, और वह मुझे बहुत सामान्य महसूस कराते हैं।

इस बीच, सेलिना ने हाल ही में बेनी के साथ अपनी शादी की योजना के बारे में खुलासा किया। द टुनाइट शो में, पॉप स्टार ने अपनी शादी की पुष्टि करते हुए कहा, 'यह शानदार है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ।' दूसरी ओर, स्टीव मार्टिन ने कहा, 'मुझे यकीन है कि हमारे निमंत्रण किसी भी दिन आ जाएँगे।' और सेलिना ने तुरंत बताया कि मार्टिन 'रिंग बियरर' होंगे।